RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-02, अंक - 31 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 07 मई 2020 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सूचना

कोरोना के संकट काल में सही खबरें लोगों तक पहुंचाना माही की गूंज समाचार पत्र का दायित्व है। इसी कर्तव्य बोध के कारण हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अखबार की पीडीएफ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे है। हालांकि यह संदेश इस समय प्रसारित हो रहा है कि समाचार पत्र की पीडीएफ शेयर करना अवैधानिक है। मैं पूरी जिम्मेदारी से स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह हमारी बौद्धिक संपत्ति है। हमारे लिए अपने समाचार पत्र के पीडीएफ संस्करणों को शेयर करना पूर्णतः वैधानिक है। कृपया रुकें नहीं, शेयर करना जारी रखें।

श्रीमती अलका संजय भटेवरा
प्रकाशक, माही की गूंज

देश में कोरोना के रिकार्ड 2958 नए मामले, मृतकों की संख्या 1694 हुई

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर में कोरोना वायरस 'कोविड-19' महामारी से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 2958 नए मामले सामने आए हैं तथा इस दौरान 126 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1694 हो गई है।

देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 49, 391 मामलों की पुष्टि हुई है। जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना से संक्रमितों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज आई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1456 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 14,183 पर पहुंच गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे है और पिछले एक दिन में 984 नए मामलों के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 15525 पर पहुंच गई है और इस दौरान 34 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 617 हो गई है। वहीं राज्य में 2819 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं।

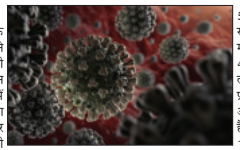

गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 441 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या के मामलों में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। गुजरात में संक्रमितों की कुल संख्या 6245 हो गई है तथा 49 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 368 पर पहुंच गई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं और पिछले 24 घंटो में 206 नए मामले दर्ज किये जाने के कारण अब तक कुल 5104 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और यह संख्या 64 पर बनी हुई है। जबकि अब तक कुल 1468 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 97 नये मामले सामने आये है और इनका आंकड़ा बढ़कर 3158 हो गया। राज्य में संक्रमण से 12 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 89 हो गई है। तमिलनाडु में 508 नये संक्रमित मामले सामने आये है और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4058 हो गई तथा अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इस वायरस की चपेट में अब तक 3049 लोग आ चुके है तथा पिछले 24 घंटों के दौरान 11 और संक्रमितों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 176 हो गयी है।

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 104 नये मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2880 हो गई है तथा कोरोना से छह और लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 56 हो गयी है। वहीं राज्य में अभी तक 987 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 11 नये मामले सामने आये और कुल संक्रमितों की संख्या 1096 हो गयी तथा मृतकों की संख्या में कोई इजाफ नहीं हुआ और यह संख्या 29 पर बनी हुई है। केरल में इस अवधि में दो और नये मामले सामने आये है और संक्रमितों की संख्या 502 हो गई है और मृतकों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है यह संख्या चार पर बनी हुई है।

दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में 1717 और कर्नाटक में 671 लोग संक्रमित हैं तथा इन राज्यों में कोरोना से मरने वालों की संख्या क्रमशरू 36 और 29 हो गयी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में संक्रमितों की संख्या 741 है और अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 140, इसके अलावा पंजाब में 25, हरियाणा में छह और बिहार में चार, झारखंड में तीन, हिमाचल प्रदेश में दो तथा मेघालय, ओडिशा और असम में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

कोरोना वायरस ने तोड़ा रिकॉर्ड, 5 दिन में 526 की मौत

देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण और मौतों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 5 दिनों में 526 लोगों की मौत, जबकि 11 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं, दुनियाभर में भी मौतों का आंकड़ा ढाई लाख के पार पहुंच गया है।

आरोग्य सेतु एप निजता का गंभीर उल्लंघन : कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने कहा है कि आरोग्य सेतु एप में हमारा डाटा सुरक्षित नहीं है और इसमें हमारी निजता का उल्लंघन हो रहा है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को कहा कि इस एप को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे साफ हो गया है कि इसमें हमारी निजता सुरक्षित नहीं है और निजता के मौलिक अधिकारों का यह गंभीर उल्लंघन है। इसको लेकर एक हैकर ने बताया कि इसमें निजता सुरक्षित नहीं है और देश की कम्प्यूटर रिस्पांस टीम ने उससे जो जानकारी मांगी थी उसने उनका जवाब दिया है।

उन्होंने कहा कि यह एप 24 घंटे हमारी गतिविधियों पर एक जासूस की तरह नजर रखता है। इसका निर्माण सरकारी क्षेत्र की नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनी ने किया है। गोआईबीबो और मेक माई ट्रिप्स ने भारत सरकार के लिए इस एप को बनाया है और सबको मालूम है कि इन दोनों कंपनियों में 40 फीसदी मल्कियत चीन की है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस एप में जो डाटा पहुंच रहा है वह कहां जा रहा है इसकी किसी को जानकारी नहीं है और भारत सरकार भी इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है।

सत्रह मई के बाद क्या कदम उठा रही है सरकारः सोनिया

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि तीसरे चरण का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सरकार इस मसले पर क्या रणनीति अपना रही है इसका उसे खुलासा करना चाहिए।

श्रीमती गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोराना वायरस 'कोविड-19' और लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि 17 मई के बाद क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को मापने के लिए क्या मापदंड अपना रही है और वह इस बारे में 17 मई के बाद क्या और कैसी नीति अपना रही है।पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीमती गांधी का समर्थन किया और कहा कि अब यह जानने की आवश्यकता है कि तीसरे चरण का लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या होगा।

लॉकडाउन के बाद नई रणनीति बनाने में जुटी मोदी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन के बाद की नई रणनीति बनाने में जुटी है। इसमें बंद के दौरान दी जा रही छूट की स्थितियों का अध्ययन हो रहा है। छूट में बढ़ती भीड़ चिंताजनक है जो संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती है। ऐसे में अति महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए सेक्टरवार व्यवस्था बनाई जाएगी जबकि आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण सेक्टरों को लंबे समय तक बंद रखा जा सकता है। वैक्सीन आने तक दो गज की दूरी सबसे बड़ा मंत्र है, लेकिन आबादी के दबाव से जूझ रहे देश में थोड़ी छूट में इंच भर की दूरी मुश्किल दिख रही है। लॉकडाउन को अनंत समय तक लागू नहीं रखा जा सकता है, ऐसे में लोगों को इसके साथ जीने के लिए तैयार करना होगा। लोगों को खुद ही नियमों का पालन करना होगा। जैसे स्वच्छता अभियान को लिया गया, उसी तरह अब दो गज की दूरी है जरूरी, सतत रूप से हाथों को धोना और मास्क का प्रयोग जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लोगों को डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन प्रयोग पर जाना होगा।

शराब की बिक्री से सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है लेकिन उसकी बिक्री में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उसे भी रोकना होगा। इसे रोकने के लिए ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत कर दी है और अन्य राज्यों में भी इसे शुरू किया जा सकता है। विशेषज्ञों की राय है कि भारत को अलग व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें वह आत्मनिर्भर हो सके। कई राज्यों ने खर्चों में कटौती शुरू की है। आगे चलकर अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में खर्चों में कटौती की गई है। राज्यसभा सचिवालय और उप राष्ट्रपति कार्यालय में भी कटौती हो रही है। धीरे-धीरे अनावश्यक खर्चों को कम करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार लॉकडाउन के बाद व्यापक रणनीति में उन सेक्टर की पहचान कर रही है जहां ज्यादा भीड़ जुटती है, लेकिन जिनको कुछ समय स्थगित रखा जा सकता है। साथ ही सम-विषम व्यवस्था भी लागू हो सकती है। बाजार, दफ्तर, यातायात आदि में इसे प्रयोग में लाया जा सकता है।

छः माह की बच्ची के लिए निकली दुआएं...

माही की गूंज, कुशलगढ़।

नए कोरोना के मामलों में नगर की एक 6 माह की मासूम बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव निकली। जिसके बाद से नगर में मासूम को जल्दी स्वास्थ्य होने के लिए लोगो ने दुआएं की। एक फोटो कोरोना पॉजिटिव 06 माह की बच्ची को दूर से निहारते बच्ची की माँ का फोटो वाइरल हुआ हैं। फोटो को देख कोरोना की भयवाह स्थिति को समझा जा सकता हैं।

झाबुआ जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव ग्राम नाहरपुरा पहुंचा स्वास्थ्य अमला

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद के साथ ही झाबुआ जिले के लिए बुरी खबर। पेटलावद के गांव नाहरपुरा में नयागांव से आए मजदूरों में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि 19 लोगों की सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे थे। जिसमें से आज सुबह 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी किंतु दूसरी रिपोर्ट में नाहरपुरा की एक महिला मजदूर पॉजिटिव आई है। अब तक झाबुआ जिला ग्रीन जोन में था, किंतु कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब प्रशासन में हड़कम्प की स्थिति हैं। दो दिन पहले भी नाहरपुरा में कोरोना पॉजिटिव की खबर न्यूज चौनलों पर चल चुकी थी, लेकिन प्रशासन बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। खबर के गलत होने पर किसी अधिकारी ने प्रेस रिलीज करके खंडन नहीं किया था। जिससे शंका के बादल बने हुए थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब मजदूरों की जांच रिपोर्ट भेजी भी नहीं गई थी, जब कोरोना पॉजिटिव की खबर आ गई थी। पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका भी संदिध नजर आ रही हैं।

प्रवासी मजदूरों को लाने में हुई बड़ी चूक

बाहर से मजदूरों को लाने में हुई प्रशानिक चूक का खामियाजा अब विकासखण्ड की जनता को भुगतना पड़ सकता है। अब तक ग्रीन झोन में शामिल जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कम्प की स्थिति हैं। ताबड़तोड़ पूरा स्वास्थ्य अमला पेटलावद से कुछ ही दूरी पर स्थित नाहरपुरा पहुंचा और पूरे गांव को सील किया गया। साथ ही पॉजिटिव महिला के परिवार को आइसोलेट किया जाना हैं। वही परिवार के आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को होम कोरोन्टाइन किया गया है। अब नाहरपुरा में 24 घंटे पुलिस का पहरा लगाया जाएगा। जिसके बाद दूसरी चुनौती शुरू होगी महिला के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार करना है। जानकारी मिल रही है कि महिला घर आने के बाद पेटलावद, केशरपुरा,अमरगढ़ आदि गावों में गई थी। जिसकी पुष्टि संपर्क में आए लोगों की सूची आने के बाद ही हो पाएगी।

परिवार के और भी सदस्य थे शामिल

कोरोना पॉजिटिव निकली महिला अकेली नयागांव से नहीं आई थी। बताया जा रहा है उसका परिवार भी उसके साथ आया था। प्रशासन ने मजदूरों को लाने की बाद भारी लापरवाही दिखाई। जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। वही मजदूरों के नाम पर की गई राजनीति पर भी अब सवाल खड़े होने लग गए है कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में लोगों की जान को खतरे में भी डालने से नहीं चूकते है ये नेता। नयागांव से आए मजदूरों की जांच दोबारा होना चाहिए। साथ ही उन लोगों को ट्रेस करना भी जरूरी हैं, जो 29 अप्रेल को नयागांव नीमच से आए थे।

भारतीय व्यवस्थाओं में सेंध लगाने वाला बांग्लादेशी सरगना अजीत राय

बांग्लादेशी माता-पिता को खवासा के अनापत्ति -पत्र पर पश्चिम बंगाल में बनाया मूल निवासी

माही की गूंज, खवासा।

बांग्लादेश के लोखईडंगा थाना मोनीरामपुर जिला जसूर का मूल निवासी सरगना अजीत राय एवं परिवार की षड्यंत्रकारी कारस्तानियां एक के बाद एक सामने आती जा रही है। माही की गूंज प्रमुखता के साथ मामले को उजागर भी कर रहा है। 23 अप्रैल के अंक में 'बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया है तथाकथित बंगाली डॉक्टर अजीत राय', 'दलालों के माध्यम से आया डॉक्टर, फर्जी डाक्यूमेंट के आधार पर डिग्रियों के साथ ही फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया।' 30 अप्रैल के अंक में 'घुसपैठिए अजीत राय नें बांग्लादेशी समधन की क्वारंटाइन के समय छुपाई पहचान', 'बांग्लादेशी घुसपैठिए ने आखिर कैसे बनाए फर्जी दस्तावेज? यह है जांच का विषय' शीर्षक के साथ गूंज ने समाचार प्रकाशित किए।

जिसके बाद सरगना अजीत राय की तरह पूरे भारत में सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। वहीं अब अजीत राय हमारी लेखनी को रोकने के लिए बड़े प्रलोभन के साथ हमारे आगे घड़ियाली आंसू भी बहाने लगा है, लेकिन माही की गूंज, घुसपैठिए अजीत राय की तरह हमारे देश के साथ किसी भी स्थिति में गद्दारी नहीं करेगा।

उक्त बांग्लादेशी सरगना अजीत राय की पड़ताल गूंज ने शुरू की तो परत दर परत कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। प्रलोभन देकर बिना किसी भारतीय मूल के पुख्ता प्रमाण या दस्तावेजों के ही किस तरह से षड्यंत्रपूर्वक अपना एवं अपने परिवार का नाम बांग्लादेशी आसानी के साथ भारत के स्थानीय निकायों के पंजीयन रजिस्टर में नाम जुड़वा कर भारतीय व्यवस्थाओ में सेंध लगाकर राशन कार्ड व राशन कार्ड के बाद तमाम भारतीय मूल के दस्तावेज बनवा लेते हैं। हमारा तंत्र आंख मूंदकर देश के इन गद्दारों उर्फ घुसपैठियों को संरक्षण देकर अपने कुछ आर्थिक लाभ के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी करने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। जिसका एक उदाहरण आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के थांदला जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खवासा में देखने को मिला है।

पंचायत के पंजीयन रजिस्टर में रिक्त जगह पर नाम फंसाकर अजीत राय ने अपने माता-पिता का पंजीयन करवाया।

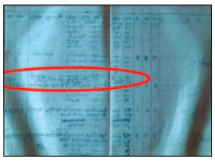

पंजीयन क्रमांक 101 बांग्लादेशी अजीत राय के 5 सदस्यों के पंजीयन के बाद नीचे लाल घेरे में 101/2 दर्शाकर रजिस्टर में भी घुसपैठ कर माता-पिता का करवाया पंजीयन।

बिना प्रमाण के ही पंचायत नें बांग्लादेशियों को भारत का मूल का निवासी बना दिया

खवासा ग्राम पंचायत के सन् 2000 के पंजीयन रजिस्टर में (पंचायत के बताए अनुसार सन् 2004) के लगभग में पंजीयन रजिस्टर के क्रमांक नंबर 101 पर बांग्लादेशी सरगना एवं फर्जी डॉक्टर अजीत राय ने स्वयं के साथ अपनी पत्नी जयंती (32 वर्ष), पुत्र विजय (11 वर्ष), पुत्री ब्यूटी (7 वर्ष), भतीजा दिपलब राय (20 वर्ष) के नाम दर्ज करवा लिए। तो वहीं इस पंजीयन में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि, 2003-04 में उसके माता-पिता बांग्लादेश में ही निवासरत थे पर अजीत राय ने अपनी कारस्तानियों के साथ पंजी. रजिस्टर में छोड़ी गई जगह पर लकीर खींचकर एक ही कॉलम में नाम फंसाकर अपने माता-पिता का पंजीयन नंबर 101ध्2 दर्शाकर अजीत राय ने उसके पिता अनंत राय (68 वर्ष) उसकी मां श्रीमती निर्माला (62 वर्ष) का पंचायत में पंजीयन करवा लिया और दो कूपन एक स्वयं अजीत राय जिसमें पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं भतीजा का 5 सदस्य दर्शाकर बनाया। तो वहीं दूसरा कूपन 101ध्2 उसके पिता अनंत राय एवं मां निर्माला 2 सदस्य का राशन कार्ड अलग से पंचायत से बनवा लिया। पंचायत ने उक्त पंजीयन के लिए इन बांग्लादेशियों से भारतीय मूल का कोई पुख्ता दस्तावेज या कोई प्रमाण-पत्र नहीं लिया और बिना दस्तावेज के ही पंचायत रजिस्टर में पंजीयन कर बांग्लादेशियों को भारतीय मूल का दर्शा दिया।

राशन कार्ड बनाने के बाद बांग्लादेशी अजीत राय ने परिवार के सभी नाम से सभी भारतीय मूल के सभी दस्तावेज मूल निवासी से लेकर परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि बना लिए।

माही की गूंज की पड़ताल में सामने आया कि, 2003-04 में घुसपैठिया अजीत राय के साथ पत्नी, पुत्र-पुत्री व जिसे भतीजा बताया गया दिपलब राय, घुसपैठ कर खवासा आए थे। लेकिन फर्जी पंजीयन के समय उसके माता-पिता बांग्लादेश में ही निवासरत थे। जिनका पंजीयन भी 101/2 में करवा कर राशन कार्ड व समस्त भारतीय मूल के दस्तावेज बनवा लिए। 7 नवंबर 2014 में अपने माता-पिता का नाम खवासा पंजीयन रजिस्टर से निरस्त करवा कर, खवासा पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने माता-पिता को भारतीय मूल का दर्शा कर, खवासा पंचायत के अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर पश्चिम बंगाल का मूल निवासी बना दिया। जब गूंज ने स्थानीय व्यक्तियों व आस-पड़ोस के रहवासियों से छानबीन की तो बताया कि अजीत राय सर्वप्रथम खवासा में किराए के मकान में आकर तीन-चार साल तक रहा। जब तक उसके माता-पिता खवासा में कभी नहीं आए। कृष्णर मोहल्ले में पुराना मकान लेकर अजीत राय ने नया मकान बनाया। जिसके बाद साल भर में एक बार 15 दिन, महीना या अधिकतम 2 महीना रह कर वापस जहां से आते थे, वहां उसके माता-पिता चले जाते थे। इस संबंध में पड़ोसी कन्हैयालाल प्रजापत ने भी बताया कि, अजीत राय फर्जी डॉक्टर है और इसके यहां कई लोग बाहरी आते हैं। इसके माता-पिता नए मकान बनने के बाद साल भर में एक बार आते थे और कुछ दिन रुक कर वापस चले जाते थे।

गूंज के विशेष सूत्रों ने बताया कि, उसके माता-पिता को दलालों के माध्यम से प्रतिवर्ष एक बार बांग्लादेश के चोर रास्ते से भारत में घुसपैठ करवा कर, खवासा तक अजीत राय लाता था। विश्वसनीय सूत्रों अनुसार खवासा में अजीत राय ने पक्का मकान बनाने के तीन-चार वर्ष बाद पश्चिम बंगाल में प्लाट लेकर मकान बनाया। पूरा मकान बनने के बाद उसके माता-पिता का ग्राम पंचायत खवासा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पश्चिम बंगाल का मूलनिवासी बनाया। तो वहीं पंजीयन में जिसे अपना सगा भतीजा दिपलब राय को बता रहे हैं वह भी बांग्लादेशी होकर अजीत राय का सगा भतीजा भी नहीं है।

प्रिंट मीडिया से जुड़े होने पर गर्व, किंतु दबती पत्रकारिता चिंताजनक

माही की गूंज, झाबुआ।

वर्तमान में हालात ऐसे हो चले है कि मीडिया को कोई भी व्यक्ति, समाज, संगठन चाहे वह किसी भी स्तर का अथवा देश के किसी भी कोने का हो, आसानी से न सिर्फगलत ठहरा देता वरन उस पर नाना प्रकार के आरोप भी लगा देता है। आरोप लगाने का फोरम भी उसे सोशल मीडिया के रूप में मिल चुका है, जिसका उपयोग इन दिनों देश का एक बड़ा तबका कर भी रहा है। सोशल मीडिया की स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत इसका उपयोग करने वाले पत्रकार बन बैठे है। पत्रकार से आशय जानकारी, घटनाएं और दुर्घटनाएं ही नहीं अपितु राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत और धार्मिक गतिविधियों की सूचनाओं और घटनाओं आदि की जानकारी सोशल मीडिया पर फेंकने वालों की कोई कमी नहीं है। यह वहीं लोग है, जो पत्रकारिता को आए दिन कटघरे में खड़ा करते है। वर्तमान में देश के हालात ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और धार्मिक नफरतें इन दिनों सर चढ़कर बोल रही है। सोशल मीडिया तो ऐसे मुद्दे ढूंढने को हर समय तत्पर ही रहती है। यही कारण है कि छोटी-मोटी घटना कांपी और पेस्ट होते-होते राष्ट्रीय मुद्दा तक बन जाती है, बगैर यह जाने कि जहां घटना घटित हुई वहां का वातावरण क्या होगा, वहां के लोग, शासन-प्रशासन और राजनीति का स्तर क्या होगा। सोशल मीडिया जो सत्य की अपेक्षा झुठ का पुलिंदा सर्वाधिक छोटी-मोटी घटनाओं को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर माहौल खराब करने में जबरदस्त योगदान देता है। हालांकि पत्रकारिता भी कटघरे में है, किंतु सर्वाधिक झूठ परोसने का श्रेय सोशल मीडिया को ही जाता है। पत्रकारिता भी इससे कहीं न कहीं काफी हद तक जुड़ी हुई किंतु देश में अभी जो सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है, वह सोशल मीडिया ही है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो लोग-लोग दिनभर सोशल मीडिया पर व्यतीत करते है, उन्हें इसकी लत लग गई है और इन लोगों को मनोरोग चिकित्सक की सख्त आवश्यकता भी है। ऐसे लोग जो दिन में दहाई अथवा सैकड़ा तक अपने विचार सोशल मीडिया पर रखते अथवा कॉपी पेस्ट करते है या वह लोग जो सुबह उठते ही बजाय धार्मिक गतिविधि एवं नित्य क्रिया के, सोशल मीडिया की ओर आकर्षित होते है। झुठ व अफवाह सर्वाधिक परोसने वाली सोशल मीडिया के बाद पत्रकारिता से विश्वास उठाने वालों में ऑनलाईन चलने वाले मीडिया पोर्टल्स का योगदान भी अधिक है। चूंकि यह पोर्टल सोशल मीडिया के समानान्तर होते है और कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना पोर्टल बनाकर उसका प्रचार करना प्रारंभ कर सकता है। साथ ही इस प्रकार के पोर्टल्स को विधि सम्मत किसी प्रकार की कोई मान्यता भी नहीं रहती है। स्वयं का प्रचार करने तथा त्वरित परोसने के साथ नाम कमाने की प्रवृति अधिकांशतः झुठ परोस बैठती है और पत्रकारिता को बदनाम करने में अच्छा खासा योगदान दे जाती है। सोशल मीडिया और ऑनलाईन चलने वाले स्तरहीन पोर्टल्स के बाद नम्बर आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। पूरा देश जानता है बड़े मीडिया समूह जो इलेक्ट्रानिक मीडिया के संचालक है, का दूर-दूर तक मीडिया से कोई नाता रहा ही नहीं है। यह सभी लोग आर्थिक उद्देश्य से इनका संचालन कर रहे है। जिनकी जिम्मेदारी देश, समाज के प्रति शून्य है। हालांकि इनसे जुड़े हुए जमीनी मीडियाकर्मी जरूर सत्य से रूबरू कराने का प्रयास करते रहते है, किंतु सत्य प्रसारित होगा या नहीं इसका निर्णय इन्हीं कथित पत्रकार उर्फआर्थिक उद्देश्य से बाजार में उतरे दुकानदार करते है। सोशल मीडिया ने देश को गर्त में डाला जिसका पूरा समर्थन ऑनलाईन पोर्टल करने लगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें मसाला ही मिला रहा है। देश का माहौल बनाने और बिगाड़ने में इन लोगों का गजब का योगदान है और शक्ति भी।

पत्रकारिता को ह्रास लगाते इन सब पहलुओं में प्रिंट मीडिया अभी तक तो बचा हुआ ही है। हालांकि भागती-दौड़ती इस जिंदगी में प्रिंट मीडिया के महत्व में अथवा यूं कहे की प्रिंट मीडिया के पाठकों में भारी कमी आई है। किंतु तथ्यात्मक और सत्य से यदि रूबरू होना हो तो अभी भी प्रिंट मीडिया सबसे आगे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही प्रिंट मीडिया के कई बड़े बैनर ऐसे भी जिनका मालिकों का उद्देश्य सिर्फआर्थिक हित ही है और इन लोगों का पत्रकारिता से कहीं से कहीं तक जुड़ाव है ही नहीं। हालांकि मीडिया समूह में कार्य करने वाले कई सारे लोग पत्रकार ही होते हैं, परंतु उनकी पत्रकारिता दबी हुई होती है। प्रिंट मीडिया में निचले स्तर का संवाददाता सत्य प्रकाशित करने हेतु जी-तोड़ मेहनत भी करता है, किंतु बड़े बैनरों का संचालन करने वाले निचले स्तर के संवाददाताओं के पर कतर देते है। यही कारण है कि कई बार चाह कर भी अंतिम पंक्ति में कार्यरत प्रिंट मीडियाकर्मी सत्य से परे हो जाता है। इसके बाद भी इन मीडिया समूह में बड़े पदों पर बैठे पत्रकार कम नौकर बजाय जमीनी हकीकत पर अध्ययन करने के, वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर यह तय करते कि यह हमारे बैनर के लिये सही है या नहीं। प्रिंट मीडिया में कई ऐसे छोटे बैनर भी जो सत्यता को बेबाकी के साथ लिखते। ऐसे बैनरों में उनकी संख्या ना के बराबर होती, जिनका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक हित ही रहता है। सत्य का प्रहरी यह बैनर कड़वा लिखने से गुरेज नहीं करता और न ही तीखा लिखने से परहेज। पत्रकारिता की एक और जमात हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार कहलाती है। वरिष्ठता का ताज लिए इसमें ऐसे लोग रहते हैं, जो वर्षों से लगातार पत्रकारिता से जुड़े हुए होते है। तथ्यों को यदि जानना हैं तो इन लोगों की कलम पढ़ना आवश्यक है। यह लोग अपनी कलम में हमेशा सत्य को प्राथमिकता देते है। सीधे पाठकों तक अपने विचार पहुंचाने की कार्यशैली भी इन्हें सत्यता से बांधे हुए रखती है। कई बार जानकारी तो ऐसी तत्थात्मकता से परिपूर्ण होती है, मानो अपने विचार लिखना ही भूल गया हो। प्रिंट मीडिया का एक तबका और स्वतंत्र पत्रकार जिनके सिर वरिष्ठता का ताज सजा है, आज भी सत्य से ज्यादा दूर नहीं भटकते और इसीलिए प्रिंट मीडिया से जुड़े होने पर हमें गर्व हैं, तो बड़े मीडिया समूह के पैरो तले दबती पत्रकारिता चिंता का विषय भी।

नयागांव नीमच से आई मजदूरों की बस ने खोली प्रशासनिक व्यवस्था की पोल

अधिकारियों के पास बाहर से आने-जाने वाले मजदूरों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं

माही की गूंज, पेटलावद।

मजदूरों के नाम पर हो रही राजनीति के बाद मजदूरो को लाने का काम सरकार ने शुरू किया। दोनों दल के स्थानीय नेताओं और उनके कार्यकर्ता मजदूरों को लाने का श्रेय लेने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की हवा तब निकल गई। जब 30 अप्रैल को बस द्वारा नयागांव नीमच से फंसे हुए मजदूरों के साथ दाहोद के मुस्लिम परिवार के 14 लोग बस में बैठ कर आए और अपने घर दाहोद गुजरात पहुंच गए। जहां गुजरात प्रशासन ने उनको जांच के लिए अस्पताल भेजा और 14 में अब तक सात लोग कोरोना पोजिटिव आ चुके है। उक्त खबर जिले में आते ही हड़कम्प मच गया। मामले में नीमच और झाबुआ प्रशासन ने इसे बस कन्डटर की गलती बताकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मजदूरों को बाहर के राज्यो से लाने की प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। न केवल नयागांव से आए मजदूरों बल्कि अब तक बाहर से आए मजदूरों की जानकारी को लेकर स्थानीय प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मजदूरो को लाने के लिए किसी प्रकार की कोई पास या डिटेल्स नहीं ली जा रही हैं। वहीं बसों में सीट संख्या और सामजिक दूरी को ताक में रख कर लोगों को बसों में अधिक संख्या में ठूंस कर लाया जा रहा हैं। बस के साथ कोई जवाबदार कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई। जिससे बस ड्राइवर और कन्डक्टर रास्ते में अपने हिसाब से बस में लोगों को बैठाकर ला रहे हैं। इतना ही नहीं बस जिन जिलों के मजदूरों को ला रही। उस जिले की पहली बॉर्डर पर किसी प्रकार से जांच पड़ताल तैनात टीम द्वारा नहीं की जा रही हैं। यदि ऐसा किया जाता तो जिले के मजदूरों के साथ सफर कर दूसरें लोगों को आसानी से ट्रेस किया जा सकता था, लेकिन लापरवाह प्रशासन ने मजदूरों के आवागमन में किसी प्रकार की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। न ही क्षेत्र अनुसार आने वाले मजदूरो की पूरी प्रामणित जानकारी प्रशासन के पास हैं। जिले की बॉर्डर पर तैनात टीम आने-जाने वाले एक-एक व्यक्ति की जांच तो कर रही है, लेकिन बड़े वाहनों और मजदूरों के वाहन पर किसी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है। जिससे भारी मात्रा में लोगों को इन्ट्री जिले में हो रही हैं।

बिना अनुमति रेड और ओरेंज झोन से लोगों का आना-जाना जारी

लगातार 40 दिन से अधिक समय से दिन रात लगी प्रशासन की टीम ने अब अपनी जांच का दायरा कम कर दिया है। जिससे कई लोग बिना अनुमति अन्य जिलों से प्रवेश करने में कामयाब हो रहे हैं। उसमें कई लोग रेड और ओरेंज झोन से आ गए है। जिनकी जानकारी प्रशासन के पास नहीं है और अधिकारियों को जानकारी देने पर भी कोई रूचि नहीं दिखाई जाती है। अगर शिकायत पर किसी पर कोई कार्यवाही होती भी है तो ज्यादा से ज्यादा उनको होम कोरोन्टाइन किया जाता है और बिना अनुमति आने पर किसी प्रकार का प्रकरण आदि नहीं बनाया जाता है और न ही कोरोन्टाइन किए गए परिवार पर किसी प्रकार की नजर रखी जाती हैं। जो लोग अन्य राज्यों या जिलों से अपने रिश्तेदारों को नियमानुसार पास बनवा कर ला रहे हैं, वो भी आने के बाद नियमानुसार होम कोरोन्टाइन नहीं हो रहे हैं। बात करें तो पेटलावद में पिछले दिनों रतलाम, उज्जैन, इन्दौर सहित अन्य राज्यों से भी लोग दबे पांव आ गए है, लेकिन नियमानुसार इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

13 अप्रैल को नाबालिक की आत्महत्या में लड़की के पिता ने लगाए हत्या के आरोप

हत्या को आत्महत्या दिखाकर मामले को दबा रही पुलिस

एसडीओपी को कार्यवाही के लिए दिया आवेदन

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश ग्रेहलोत

पिछले दिनों सारंगी चौकी के अन्तर्गत अवैध शराब कांड में एक व्यक्ति की मौत के बाद सारंगी पुलिस पर शराब ठेकेदार के लोगों के साथ मिलकर हत्या करना का गंभीर मामला के सामने आने के बाद एक और नया मामला सामने आया है। जहां सारंगी पुलिस पर एक नाबालिक लड़की की हत्या के मामले को दबाने के गंभीर आरोप नाबालिक के परिवार और उसके पिता ने लगाए हैं।

पेटलावद थाना अन्तर्गत सारंगी चौकी में 13 अप्रैल को ग्राम माण्डन निवासी भेरू डामोर की नाबालिक पुत्री मंजू डामोर का शव खेत पर लगे बबूल के पेड़ से लटका मिला। जिसे पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में आत्महत्या पाकर मामला दर्ज कर लिया। लेकिन मृतक के परिवार के सामने घटना की प्रत्यक्षदर्शी एक महिला द्वारा हत्या का खुलासा करने के बाद मृतक नाबालिक के पिता ने 19 अप्रैल को सारंगी चौकी पर लिखित आवेदन दिया। जिसके अनुसार ग्राम माण्डन के ही सरदार ताड़, भुला ताड, और एक अज्ञात लडकी द्वारा हत्या को अंजाम देने की बात बताई गई। परिवार का आरोप है कि सारंगी चौकी प्रभारी ने मामले को दबाने के लिए हत्या को अब तक आत्महत्या बता रखा है और किसी प्रकार की कार्यवाही हत्या को अंजाम देने वालों पर नहीं की गई।

इस संबंध में मृतक नाबालिक के पिता भेरू डामोर ने एसडीओपी कार्यालय पेटलावद में 05 मई को आवेदन देकर बताया कि सरदार ताड द्वारा 12 अप्रैल को मेरी पुत्री के साथ छेडखानी की गई थी। जिसका विरोध मेरी पुत्री ने किया था और घर आकर इस बारे में बताया भी था। लेकिन मेरे द्वारा लड़की की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अगले दिन मेरी लड़की जब खेत पर गई तो वापस नहीं आई और उसकी आत्महत्या की खबर आई। पिता का कहना है कि मेरी पुत्री ने आत्महत्या नहीं की है। उसकी हत्या की गई। जिसकी जानकारी पास के गांव कोटडा में रहने वाली नंदुडी पति जालु गरवाल ने दी है कि उसने आरोपियों को हत्या करते देखा। लेकिन हत्या करते देख नंदुडी बुरी तरह घबरा गई और चार दिन तक किसी को यह बात नहीं बताई। अब जब बात नंदुडी द्वारा बताई तो चौकी पर आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई हुई।

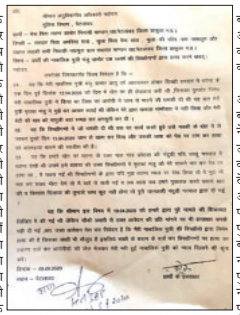

नाबालिग की हत्या का प्रकरण दर्ज करने हेतु एसडीओपी कार्यालय में लड़की के पिता द्वारा दिया गया आवेदन।

मामले में अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी बता रही नंदुडी गरवाल ने गूंज को बताया कि उसने आरोपियों को मंजू का शव पेड़ पर लटकाते देखा है और यह बात अपने बयान में चौकी पर भी बताई है। लेकिन पुलिस ने उल्टा मुझे झूठ बोल रही है, ऐसा कहा। नंदुडी ने बताया कि पुलिस ने उससे कहा कि नशे का इन्जेशंन देकर पूछेंगे। ऐसा कहकर पुलिस धमकाने लग गई, जबकि मेरे द्वारा पुलिस को जो देखा है, वही बताया है।

मामले में चौकी प्रभारी श्याम कुमावत से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ मारपीट की गई और उसे धसीटा गया। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या जैसा कुछ नहीं आया है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट आना बाकी है।

परिवार ने लगाए जांच में लापरवाही के आरोप

मृतक लड़की के पिता भेरू डामर ने बताया कि पुलिस ने जांच में लापरवाही की है और साक्ष्य को पूरी तरह से अनदेखा किया। मेरी पुत्री का शव जिस पेड़ से मिला। उसके चप्पल उसी के शव के नीचे थे। जिसे पुलिस ने हटाकर पेड़ के तने के पास रख दिए। पेड की जिस साख से लाश लटकी मिली, वो जमीन से लगभग 15 फीट ऊंचा है और इतने से उसे से फंसी के फंदे पर झुलने से गर्दन तक टूट सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लटके हुए शव के पैर जमीन से एक फीट ऊपर थे। जहां काटेदार झाडियां थी और पैर उन झाडियों के अंदर तक थे, लेकिन लडकी के पैर पर किसी प्रकार की कोई रगड या निशान नहीं बने थे। परिवार का खुला आरोप है कि प्रत्यक्षदर्शी होने के बाद भी पुलिस हत्या का मामला दर्ज नहीं कर रही है। उल्टा उसे डरा रही है। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। शंका के घेरे में क्यों है सारंगी पुलिस बताएंगे अगली खबर में। *निरन्तर.....*

प्रशासन ने 2 बजते ही कराया बाजार बंद

माही की गूंज, मेघनगर। भूपेंद्र जैन

4 मई को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कलेक्टर के आदेश अनुसार मेघनगर में प्रशासन ने लोगों को समझाइश देते हुए नगर बंद कराया। पैदल भ्रमण कर निर्धारित समय दोपहर 2रू00 बजे दुकाने बंद कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी गरण जैन की टीम में नायब तहसीलदार अजय चौहान, मुख्य नगर पालिका विकास डावर, एसडीएम सहायक राजेंद्र सिंह टांक और स्वच्छता विभाग पर्यवेक्षक माधव सिंह हिरवा एवं पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। जिन्होने पूरे नगर में पैदल मार्च कर सख्ती से लॉक डाउन के नियमों का पालन करने की समझाइश दी।

कोरोना वारियर्स को नहीं मिल रही सुरक्षा सामग्री

माही की गूंज, झाबुआ। कोविड-19 के तहत गुजरात सीमा पर पिटोल बैरियर पर कोरोना ड्यूटी में लगे हुये स्वास्थ्य कर्मचारी एवं पुलिस, पटवारी ओर कोटवार, आयुष डॉक्टर,आदि की जिदगी दाव पर लगी हुई है। किन्तु जिला प्रशासन की ओर से इन कोरोना ड्यूटी में लगे हुये सैकडो कोरोना वारियर्स को ना तो मास्क दिये गये ओर ना ही पीपीटी किट प्रदान किये गये है। जिसके चलते सेवा निवृत्त पटवारियो सहित ये लोग अपनी जान जोखिम मे डालकर वहा काम कर रहे है। इन सुरक्षा उपकरणो के अभाव में ये लोग प्रशासन का आदेश का पालन अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे है। जबकि विधिवत ऐसे लोगो को एन-95 मास्क दिये जाना चाहिये था। हालही में झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया द्वारा स्वास्थ्य विभाग झाबुआ हजारो की सख्या में एन-95 मास्क सहित पीपीटी किट आदि प्रदान किये गये है। किन्तु उक्त सामग्री वास्तविक जरूरतमंदो को नही मिल पा रही है। ओर अधिकारियो ने इस पर कब्जा कर रखा है। यदि पिटोल बार्डर पर तैनात लोगो को ये जीवन रक्षक सामग्री प्रदान करने मे लेटलाली की गई तो निश्चित ही इनके जीवन के साथ ही उनके परिवार को भी इसका खामियाजा उठाना पड सकता है। जिला प्रशासन को इस दिशा मे ध्यान देने की दरकार है।

अच्छी खबरः कोरोना पॉजिटिव 41 लोग हुए स्वस्थ्य, दो नए मामले सामने आए

माही की गूंज, कुशलगढ़। वैभव बैरागी

कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कुशलगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। अब तक नगर में मिले 65 में से 41 लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं, लेकिन क्षेत्र कोरोना से पूरी तरह से अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। पिछले दिनों 3 नए केस सामने आने के बाद 1 मई को 02 नए मामले फिर से सामने आए। जिसमें से एक 6 माह की मासूम बच्ची भी है। अभी भी नगर में कोरोना का खौफबरकरार हैं। नगर में सबसे पहले पॉजिटिव हुए पिता-पुत्र को, स्वस्थ होने के बाद 14 दिन बांसवाड़ा में क्वारटाइन करके पुनः कुशलगढ़ अपने घर भेजा गया हैं। अब तक के 65 पॉजिटिव लोगों में से 24 को उदयपुर ही उपचार के लिए रखा गया। बाकी 41 लोगों का स्वस्थ्य बिल्कुल ठीक हैं, जिन्हें बांसवाड़ा क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है।

बाकी बचे लोगों की भी जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटने की उम्मीद हैं। एक मई तक कुल 1273 सैम्पल जांच किए जा चुके हैं। आपको बता दे कि 04 अप्रैल के बाद कुशलगढ़ में कोरोना के मामले सामने आने के बाद से लगे कर्फ्यू के कारण लोग पूरी तरह से घरों में कैद है और जब तक कोरोना के मामले सामने आएंगे हालात सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। कुशलगढ़ बीसीएमओ डॉ. राजेन्द्र उज्जैनिया से हुई बात में उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1273 सैम्पल जांच किये गए। अंतिम 22 सैम्पल जिनकी जांच अभी बाकी है, वे पेंडिंग हैं।

साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पॉजिटिव मरीज के सम्पर्क में आए लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई जा रही है। उस आधार पर सैम्पल लिए जा रहे हैं। उसका कोई आंकड़ा निर्धारित नहीं है। बुधवार दोपहर तक कोई नया मामला सामने नहीं आने से लोगों ने राहत ही सांस ली है जबकि स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी और पॉजिटिव केस सामने आ सकते हैं।

ठीक हो कर आए कोरोना पीड़ितों का किया स्वागत

जो लोग कोरोना की जंग लड़ कर ठीक होकर अपने घर पहुंचे उनका नगरवासियो ने ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं प्रशासन की ओर से बधाई पत्र और पुष्पगुच्छ से बीसीएमओ डॉ. राजेन्द्र उज्जैनिया ने घर लौटे पिता-पुत्र का स्वागत किया।

सांप्रदायिक सौहार्द्र की मिशाल बना करड़ावद

23 मुस्लिम परिवार के 104 लोगों को अहसास नहीं हुआ परायेपन का, आंखे नम कर हुए विदा

माही की गूंज, पेटलावद।

जहां पूरा देश आज कोरोना के कारण संकट में है। तब्लीगी जामतियों द्वारा कोरोना को फैलाने पर देश में साम्प्रादिक बहस छीडी हुई हैं। वहीं पेटलावद विकास खण्ड के समीप ग्राम करडावद ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी मिशाल पेश की। जिसे जितना सराहा जाए कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी छोटी से छोटी सेवा को बड़ा रूप देने के इस दौर में कम ही लोग जानते है कि ग्राम करडावद के लोगों ने कैसे बिना प्रचार और स्वार्थ के मानव सेवा का परिचय दिया है।

करडावद में शीतला सप्तमी के अवसर पर लगने वाले एक दिन के मेले के लिए हर साल की तरह इस साल भी झुले-चकरी वाले आए थे। लेकिन कोरोना वायरस के चलते देशभर में हुए लॉकडाउन के चलते यहीं फंस गए। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के मुस्लिम समाज के 23 परिवार के कुल 104 लोग ग्राम करडावद में रहने पर मजबूर हो गए। जहां उनका अपना कोई नहीं था। न कोई धंधा, न खर्च के लिए पैसे। शुरू के कुछ दिनों तक तो ये लोग जैसे-तैसे अपना समय निकाल पाए, लेकिन काम धंधे नहीं होने और परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण खाने पीने तक का गंभीर संकट इनके सामने खड़ा हो गया। ऐसे में ग्राम करडावद के लोग स्वेच्छा से आगे आए और बिना किसी भेदभाव के इन 23 परिवारों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इनका पूरा सहयोग किया। इतने सारे लोगों की व्यवस्था करने में स्थानीय ग्राम पंचायत ने भी हाथ खड़े कर दिए और मात्र दाई क्विंटल गेंहूं देकर कर अपनी ओर से इति श्री कर ली। अचानक इन परिवारों पर आए संकट को देखते हुए

परविशान मिलने के बाद ट्रकों में अपने झूले वकरी के साथ रवाना होते करडावद में फंसे 23 परिवार।

अपनी ओर से उपलब्ध करावाया। कुछ दिन के लिए मानो एक नया मोहल्ला ही बस गया था। अस्थाई तंबू में रह रहे परिवारों के पास ही रहने वाले सुभाषचन्द्र ने सभी के लिए आटे और पानी व्यवस्था की। इनके टेन्ट के आसपास अंधेरा न हो तो बिजली की व्यवस्था नितिन सोलंकी ने की। तो वहीं पेटलावद से कुछ समाज सेवी अपनी ओर से इन परिवारों के लिए मास्क के रूप में राशन का सामान लेकर आए। जिन्होंने कोई फोटो तक खिंचवाने से मना कर दिया। लगभग दो माह नगरवासियों ने इनकी मदद करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने गेंहू, चावल, आटा, दाल, प्याज सहित किराने का सामन अपनी सामर्थ्य वास्तविक जरूरतमंदो को नही मिल पा रही है। ओर अधिकारियो ने इस पर कब्जा कर रखा है। यदि पिटोल बार्डर पर तैनात लोगो को ये जीवन रक्षक सामग्री प्रदान करने मे लेटलाली की गई तो निश्चित ही इनके जीवन के साथ ही उनके परिवार को भी इसका खामियाजा उठाना पड सकता है। जिला प्रशासन को इस दिशा मे ध्यान देने की दरकार है।

नगरवासियों से परेशान ये परिवार हर परिस्थिति में घर जाना चाहते थे, लेकिन सरकारी उलझनों के कारण अनुमति नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में करडावद के सुभाषचन्द्र राठौर, नितिन सोलंकी और पारस गरवाल द्वारा तीन दिन के अथक प्रयासों से सभी 23 परिवारों को अपने घर अजमेर राजस्थान भेजने के लिए पास जारी कराए और झुला-चकरी भरने के लिए 12 ट्राले की किराये से व्यवस्था कर सभी को अपने घर के लिए रवाना करवाया। जैसे ही इन परिवारों को घर जाने की अनुमति मिली। इनकी आखों से आंसू छलक गए और ग्राम करडावद के नगरवासियों का जिस तरह सहयोग मिला। उससे ये सभी करडावद के लोगों को धन्यवाद कर रवाना हुए। लगभग दो माह तक हमारे आसपास इतने लोग बाहर के रहे, लेकिन करडावदवासियों की सेवा भावना के चलते किसी भी तरह की समस्या या विवाद इन परिवारों को लेकर सामने नहीं आया। करडावद के लोगों ने इन परिवारों पर कोई आपत्ति और विपत्ति आने ही नहीं दी। देश के माहौल और बीमारी को दरकिनार कर सेवाभावना मिसाल पेश की।

चोरों ने पुलिस की गश्त के दौरान सूने मकान के ताले तोड़े

माही की गूंज, कुन्दनपुर।

ग्रामीण अंचल में अब सूने मकान चोरों के निशाने पर है। कुमहार मोहल्ले के आजाद चौक के पास एक दुकान का ताला टूटने की घटना हुई। रात्रि में करीब 3 बजे मदनलाल पंचाल के मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने में चोर नाकामयाब रहे। गांव के लोगों को पता चला कि गांव में चोर है। तो आस पास के लोगों ने हल्ला मचा दिया। जिससे चोर पत्थर मारते और टुटा हुआ ताला फेंककर भाग निकले। पुलिस को सूचना देने के लिए कुन्दनपुर चौकी प्रभारी सुशील पाठक को सूचना देने के लिए गांव के कई लोगों ने फोन लगाया, पर चौकी प्रभारी ने फोन नहीं उठाया। इसी तरह की लापरवाही रही, तो गांव में कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है।

वयोवृद्ध श्रीमती राजूबाई का देवलोकगमन

माही की गूंज, झाबुआ। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष एवं भावसार समाज के वरिष्ठ अरूण भावसार की पूज्नीय माताजी स्व. श्री मांगीलाल भावसार की धर्मपत्नि श्रीमती राजूबाई भावसार उम्र 81 वर्ष का 5 मई मंगलवार को तड़के सुबह देवलोकगमन हो गया। उन्होंने रामकृष्ण नगर स्थित नवीन वरदान हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार गैल स्थित मुक्तिधाम पर हुआ। मुखाग्नि पुत्र अरूण भावसार एवं पोते देवर्षि भावसार ने दी।

शराबी आकाओं का किया अनुसरण, सेल्समेनों द्वारा खाद्यान्न बेचने का मामला आया सामने

माही की गूंज, खवासा।

बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। यह तो बिल्कुल सत्य है कि जिस बुरी राह पर आका चलते हैं, उसका अनुसरण उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारी करते ही हैं।

ऐसा ही कुछ मामला मादलदा एवं बेडावा में पदस्थ आदिम जाति सहकारी संस्था के सेल्समेनों के कृत्य से देखने में आया है। बता दे कि, लॉकडाउन के बाद भी सीसीबी शाखा में पलीता लगाने वाले भ्रष्ट पारसिंग मुणिया जो कि बामनिया सीसीबी शाखा से थांदला ट्रांसफर होकर गया था, जिसका 3 मार्च को जन्मदिन था पर लॉकडाउन के बाद भी आदिम जाति सहकारी संस्थाओं के मैनेजरों के साथ शराब एवं मांसाहार की पार्टी की। जिसके फोटो भी मैनेजरों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जिसके बाद माही की गूंज ने मामले को प्रमुखता के साथ उठाया। तो वहीं दारू पार्टी में शामिल धामनी सहकारी संस्था के प्रबंधक राजेंद्रसिंह राठौर की अधीनस्थ सहकारी संस्था मादलदा व बेडावा की दुकान की अनियमितता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाना, साथ ही पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न नहीं देना व खाद्यान्न में हेरा-फेरी के भी समाचार प्रकाशित किए। परंतु सभी जवाबदार आका शराब पार्टी के नशे में इतने धुत है कि, वह इस परेशानी की घड़ी में जहां हर आदमी खासकर गरीब तबके का व्यक्ति परेशान हो रहा है, जिन्हें शासन की ओर से दी जा रही योजनाओं का लाभ एवं खाद्यान्न देने का दायित्व है। पर ये सभी जवाबदार नशेड़ियों ने अपनी जवाबदेही को ताक में रख दिया। नतीजन 'ढाक के वही तीन पात' का मामला चरितार्थ हो रहा है। अपने ही आकाओं का अनुसरण कर संस्थाओं के सेल्समेन और तुलावटी शराब के नशे में धुत हो रहे हैं। वरन् बिना किसी डर के खुलेआम कालाबाजारी कर संस्था की दुकान पर खाद्यान्न जाने के पूर्व ही खाद्यान्न की हेरा-फेरी वर्तमान स्थिति में भी करने से पीछे नही हट रहे हैं। 1 मई को सुरेशचन्द्र पूरणमल जैन (पप्पू सेठ) का ट्रक क्रमांक एमपी 45 एच 1050 बेड़ावा एवं मादलदा की आदिम जाति सहकारी संस्था की दुकान हेतु खाद्यान्न भरकर गया।

खाद्यान्न से भरा ट्रक लेकर भागे निशेड़ी, दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा।

नशेड़ी चालक व सेल्समेन, मजदूरो को आते देख ट्रक लेके हुए रफूचक्कर

उक्त ट्रक बेड़ावा का खाद्यान्न खाली कर मादलदा जा रहा था। मादलदा की संस्था दुकान के पूर्व ही खाद्यान्न की हेरा-फेरी करने हेतु एकांत में सूनी पड़ी झोपड़ी के वहां ट्रक रुका। वहां चावल के कट्टे उतारे ही थे कि, झोपड़ी के कुछ दूर आगे तालाब पर कार्य चल रहा था। पूर्व से ही संस्था के सेल्समेन पर आरोप थे कि पूरे के पूरे खाद्यान्न की हेरा-फेरी कर महीनों-महीनों तक संस्था से खाद्यान्न का वितरण ही नहीं करते है। इसी बीच 1 मई को सुनसान झोपड़ी के वहां ट्रक खड़ी कर चावल के कट्टे उतार रहे थे कि, तालाब पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों को ट्रक की ओर आते देख चावल के 6 कट्टे वहीं सड़क पर छोड़ सेल्समेन के इशारे पर ट्रक चालू कर भाग गए। मजदूर संस्था की दुकान पर पहुंचे, पर वहां ट्रक नहीं था। डर के मारे मादलदा में खाद्यान्न खाली किए बिना ही ट्रक को लेकर रफूचक्कर हो गए।

खाद्यान्न की हेरा-फेरी करने हेतु उतारे चावल के यह 6 कट्टे।

लोगों को किया गुमराह, ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बचा

स्थानीय लोगों ने सेल्समेन के मोबाइल पर फोन नहीं लगने के कारण तुलावटी उदयसिंग कतीजा को फोन लगाया और ट्रक की जानकारी देना चाही तो, मादलदा संस्था दुकान के सेल्समेन गुड्डु बिलवाल के इशारे पर उदयसिंग लोगों को कभी परवाड़ा, कभी भेरपाड़ा तो कभी रत्नी-भामल में ट्रक होना बताकर गुमराह करते रहे। आखिरकार ट्रक खवासा में थांदला मार्ग पर बस स्टैंड के समीप टोडा फलिये में जाने वाले रास्ते पर ट्रक का एक पहिया पुल के ऊपर तो दूसरा पहिया पुल के नीचे नहर के किनारे उतार गया। गनीमत यह रही कि, नीचे उतरे पहिए में ठेसी लग गई वरना ट्रक नहर के अंदर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था।

ग्रामीणों को ट्रक मिलने के बाद सेल्समेन गुड्डु बिलवाल से फोन पर बात हुई, तो वह अपने आप को चौकी पर होना बताया, पर वह चौकी पर भी नहीं था। ट्रक में एक हम्माल था जो इतने शराब के नशे में था कि, वह क्या कह रहा है उसे ही समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद मादलदा सेल्समेन गुड्डु बिलवाल, बेडावा सेल्समेन प्रवीण पंचाल, तुलावटी उदयसिंग कतीजा व ट्रक चालक आए, पर वे सभी शराब में इतने धुत थे कि, उनकी स्थिति कुछ बयां नहीं कर सकते? पर जब माही की गूंज प्रतिनिधि मादलदा सेल्समेन से मामले की मुंह जुबानी जानने पहुंचा तो शराब के नशे में टब्ली बिलवाल, तुलावटी व ट्रक चालक रफूचक्कर हो गए। यही नहीं बेडावा का सेल्समेन अपनी रोटियां सेंकते रहा और शराब के नशे में कहता रहा, यह मेरे यहां का मामला नहीं है और शराब के नशे में होने के बाद भी कहता रहा हम शराबी नहीं है।

उक्त मामले में सरेआम देखा गया कि, खाद्यान दुकान पर पहुंचने के पूर्व ही उसे रफू- दफ्त कर दिया जाता है। 1 मई को दोनों सेल्समेंन ने गाड़ी के चालक सहित हम्माल को भी जमकर शराब पिलाई और सभी शराब के नशे में इतने टाब्ली थे कि, किसी को कुछ समझ ही नहीं पड़ रही थी। बाद में सुरेशचंद्र जैन के मुनीम पहुंचे और ट्रक को मादलदा दुकान पर खाली किया गया।

ग्रामीणों का कहना था कि, अभी 3 महीने का खाद्यान्न दिया है। उसके पूर्व का तीन-चार महीने का खाद्यान्न दिया ही नहीं और उक्त 3 माह के खाद्यान में भी 5-5 किलो अनाज सभी को कम दिया। जिसकी शिकायत व जांच होने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की गई।

इस सम्बंध में सुरेशचंद्र जैन ने बताया कि, गाड़ी ड्राइवर ने सेल्समेन के कहने पर ही गाड़ी को रोककर चावल के कट्टे उतारे होंगे। मैं ऐसे किसी भी चालक को नौकरी पर नहीं रखूंगा, जो पैसे लेकर बेईमानी करते हैं।

पिछले 48 दिनों से ग्रीन झोन वाला झाबुआ झटके से आया ओरेंज झोन में

जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव केस पेटलावद तहसील में, सावधान खतरा अभी टला नहीं, कलेक्टर ने की आम जनता से अपील

माही की गूंज, झाबुआ।

झाबुआ जिला जो कि कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक बचा हुआ था तथा ग्रीन जोन में बना हुआ था। परंतु बुधवार को पेटलावद तहसील के ग्राम नारहपुरा में झाबुआ जिले का कोरोना संक्रमण का पहला पॉजिटिव केस आया। कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने झाबुआ जिले की समस्त जनता, किसानों तथा व्यापारियों से अपील की है कि संपूर्ण जिले में ऑरेंज जोन के नियमानुसार ही सभी को सतर्कता से कोरोना वायरस महामारी के अंतर्गत लॉक डाउन के नियमों का पालन करें। तभी हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकेंगे। अब प्रशासन के साथ-साथ जिले की जनता को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा अन्यथा हमारी लापरवाही एक भयानक रूप ले सकती है।आज भी झाबुआ जिले की जनता द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है तथा पूर्ण रूप से लॉक डाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

झाबुआ जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस कैसे आया

29 अप्रैल को नयागांव राजस्थान से एक बस झाबुआ जिले के मजदूरों को लेकर आई। जिसमें नीमच के रास्ते दाहोद के 14 लोग भी बैठे थे,जो कि गुजरात के दाहोद क्षेत्र के थे। दाहोद के 14 लोगों में से दाहोद में सात लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके साथ झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के 19 मजदूर भी बस में सवार होकर आए थे। उन सभी मजदूरों को पेटलावद चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोन्टाइन में रखा गया था तथा ब्लड सैंपल लेकर कोरोना वायरस की जांच हेतु भेजा गया था। बुधवार सुबह 27 जांच की रिपोर्ट में से 25 रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक महिला नाहरपुरा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तथा एक रिपोर्ट आना शेष है।

सीएमएचओ डॉ बीएस बारिया सहित पेटलावद बीएमओ डाक्टर एमएल चौपड़ा ने बताया कि कोरोन्टाइन महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद ही उक्त संबंध में अधिक जानकारी दी जा सकती है। झाबुआ जिले का पहला केस कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया तथा उक्त महिला के गांव नाहरपुरा को प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से सील कर दिया गया तथा सभी लोगों को चेतावनी दे दी गई है कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, । पेटलावद के नाहरपुरा में एक ग्रामीण महिला सजनाबाई को निकला कोरोना। यह महिला राजस्थान से दाहोद के कोरोना पॉजीटिव बस कंडक्टर के साथ आई थी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हुआ सख्त। पेटलावद के नाहरपुरा पंहुचे प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम। संभवत मरीज को पेटलावद स्वास्थ्य केंद्र पर आईसोलेट कर नाहरपुरा गांव को किया जाएगा पूरी तरह सील। पेटलावद के ग्राम नाहरपुरा में रहने वाली उक्त महिला को पेटलावद से सेनेटाईज की हुई एम्बूलेन्स मे जिला चिकित्सालय परिसर स्थित चिन्हन वार्ड जिसे कोरोना पॉजिटिव्ह के लिये वार्ड बनाया गया है में भर्ती कर दिया गया है। जहा जिला चिकित्सालय के मेडिकल स्पेशलिस्ट एवं चिकित्सको व स्टॉफ द्वारा उक्त महिला का उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। महिला के साथ उसका पति एवं छोटा बच्चा भी साथ में आये है। प्रशासन को चाहिये की उक्त कोरोना मरीज की आमद के साथ ही पेटलावद सहित पुरे झाबुआ जिले को सर्तकता बरतने के लिये कडे कदम उठाना होगे। तथा कोरोना मरीजो की संख्या में बढोतरी ना हो इस ओर भी आवश्यक ध्यान देना जरूरी है। प्रशासन ने ग्राम नाहरपुरा को झोन को सील्ड करने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी है। इस महिला के संपर्क में जितने भी लोग आये है उनकी हिस्ट्री लेकर उन सभी को भी कोरोनटाईन करके इनकी भी जांच करवाई जाना जनस्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी दिखाई दे रहा है।

कोरोना पॉजिटिव महिला को 108 एम्बूलेन्स में लाया जिला चिकित्सालय में।

नाहरपुरा ग्राम में पहुचे स्वास्थ्य विभाग की टीम।

मोहनखेडा तीर्थ में मुनिश्री का 24वां संयम दिवस मनाया

माही की गूंज, झाबुआ।

जैन तीर्थ मोहनखेड़ा की पावन भूमि पर परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्यदेव श्रीमद् विजय ऋषभचंद्र सूरीश्वजी महाराज साहेब की पावन निश्रा में आप श्री के शिष्य परम पूज्य मालवरत्न मधुरवक्ता मुनिराज श्री रजतचंद्र विजयजजी महाराज साहेब का 24 वा संयम दिवस जैन तीर्थ की पावन भूमि पर धूमधाम से मनाया गया। प्रातः परमात्मा का शक्रस्तव महाअभिषेक किया गया । 10रू30 से श्री राजेंद्रसूरी अष्ट प्रकारी पूजा का आयोजन गुरु दरबार मे राणीबैनुर के महेन्द्रकुमार पगालालजी संघवी आलासन वालो की ओर से धूमधाम से संगीत भक्तिमय माहोल मे किया गया। इस मौके पर प.पू.मुनिराज श्री पीयूषचन्द्र विजयजी म.सा.ने बताया मेरे बंधु मुनिराज श्री रजतचंद्र विजयजी म.सा.का 25 वां संयम वर्ष उत्सव उज्जैन (म.प्र.) में मई महीने में आयोजित होने वाला था। यह महोत्सव कोरोना महामारी के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह मे स्थगित कर दिया गया था। कमेटी सदस्य ने कहा महामारी से मुक्ति होगी उसके बाद में इस महोत्सव को आयोजित किया जाएगा । अभी वर्तमान में गुरुदेव श्री एवं मुनि मंडल साध्वी मंडल मोहनखेड़ा तीर्थ में विराजमान है । पूजन के पश्चात् आदिवासी गरीब परिवारों को भोजन के पैकेट एक परम गुरुभक्त परिवार की ओर से वितरित किए गए। गुरुदेव श्री के वडिल शिष्य मुनिराज श्री पीयूषचंद्र विजयजी महाराज साहेब मुनिराज श्री रजतचंद्र विजयजी महाराज साहेब मुनिराज श्री पुष्पेंद्र विजयजी म.स.मुनिश्री रूपेंद्र विजयजी. मुनिश्री जीतचंद्र विजयजी जनकचंद्र विजयजी ने गुरुपूजा में गुरु भक्ति गीत से अनुपम माहौल बनाया।

जहांपना अब तो मान ही लो कि गलती आपकी है, हम तो 15 दिनों से चिल्ला रहे है

माही की गूंज, झाबुआ। मुज़म्मील मंसूरी

आखिरकार जिस बात का डर था, वह हो ही गया। 40 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन झेलने के बाद जिले को प्रशासन ने तोहफे में जो दिया वह मौत का मुहाना ही है। देश, प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकारों की गलती साफ दिखाई दी, तो जिले में प्रशासन की गलती से आज जिले के 11 लाख लोगों की जान सख्ते में आकर खड़ी है। हम अपने पिछले अंकों में प्रशासन को कई बार इस बात को लेकर चेताते रहे कि जिले की सीमाएं पूर्ण रूप से सील कर दी जाए और जिले को लॉकडाउन में छूट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिले की सीमाओं पर किसी भी तरह की कोई सिलिंग नहीं की गई। गुजरात से आने वाले मजदूर जिले में लगातार आते रहे लेकिन जहांपना ने सिर्फ गुजरात की मुख्य बॉर्डर पिटोल पर अपनी फोर्स तैनात कर दी और बाकी के सभी रास्ते आधी अधूरी सख्ती के साथ खुले छोड़ दिए। जब प्रशासन द्वारा मुख्य मार्ग पर सख्ती की गई तो पैदल आ रहे मदजूरों ने जंगलों का रास्ता चुना और जिले में बेधड़क प्रवेश करते चले गए। तब भी हमने जिले के जहांपना को चेताया था और बताया था कि आने वाले मजदूर कहीं जिले को संक्रमण के दलदल में न धकेल दे। मगर उस वक्त भी प्रशासन या जहांपना के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रशासनिक अमला सिर्फ मुख्य मार्ग पर मजदूरों की स्क्रीनिंग करता रहा। ये तो भला हो उन जागरूक ग्रामीणों का जो गांव में किसी के आने पर प्रशासन को सूचित करते रहे। मगर गुजरात से आने वाले मजदूरों में केवल जिले में मजदूर नहीं थे, यहां तो प्रदेश के अन्य जिलों व अन्य प्रदेशों के मजदूर भी आने लगे। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कई कोरोन्टाइन सेंटर बनाए और अन्य जिलों व प्रदेशों के मजदूरों को इन सेंटरों में कई दिनों तक रखा।

अब जब प्रदेश सरकार ने मदजूरों की वापसी की बात कही तो हालात कुछ ऐसे बने कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में तो ठीक प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में मजदूरों की आवाजाही बढ़ गई। प्रशासन ने मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया और यहीं से जिले में संक्रमण आने का दरवाजा खुल गया। जिस जिले से मजदूर झाबुआ जिले में आए उस जिले के प्रशासनिक अमले ने तो गलती की, लेकिन वही गलती झाबुआ जिला प्रशासन ने भी उन मजदूरों के आने पर की। कुल मिलाकर हुआ यह कि आने-जाने वाले मजदूरों की कहीं भी किसी भी तरह से गंभीर जांच नहीं की गई। देश में पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, लोग अपने घरों में कैद है, तो फिर यह संक्रमण कहां से और कैसे फैल रहा है। यह प्रश्न सरकारों और प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। यह इस बात की बानगी है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक कोई भी सजग नहीं है। सिर्फ एक हल्ला मचा दिया गया लॉकडाउन। इसके अलावा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जो इस संक्रमण को रोक पाने में सक्षम हो।

जिले में कोरोना की दस्तक जिला प्रशासन की खुली लापरवाही का ही नतीजा है। मगर जहांपना तो अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए है। बीरबल जहांपना को चने के झाड़ पर चढ़ाता रहा और जहांपना भी चढ़ते ही चले गए। हमने कई बार जहांपना को रोकने और समझाने की कोशिशें की मगर क्या करें? जहांपना तो कामयाबी का सेहरा अपने सिर बंधवाना चाहते थे। जहांपना ने जिले की जनता का खूब मजाक बनाया। बेवजह लॉकडाउन में तरसाया, ललचाया और खूब टूंगाया। लेकिन अब नाव में छेद हो गया है और यह अब नाव को कितना नुकसान पहुंचाता है यह समय के गर्त में है। हां इतना जरूर है कि जहांपना ने अपनी वाहवाही के चक्कर में सत्तनत को ही दांव पर लगा दिया है।

खैर यह तो आज जिले में पहला मामला कोरोना संक्रमण का सामने आया, लेकिन इससे पहले कई बार हम अपने अखबार के माध्यम से इस बात को उठा चुके है कि जिले की सीमाएं पूरी तरह सील नहीं है। इसके कई प्रमाण भी हमने अपने अखबार में दिए। राजस्थान की सीमाओं से आवाजाही हो या शराब तस्करी का मामला, थांदला में ईंट भट्टों पर काम करने आए नीमच, मंदसौर, उज्जैन जैसे संक्रमित जिलों के मजदूरों का मामला या धार जिले के राजोद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के जरिए पेटलावद क्षेत्र में आ-जा रहे मजदूर व अन्य लोगों का मामला। हमने हर मुद्दे पर प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन से अपील भी की थी कि जिले की सीमाएं सील की जाए। बावजूद इसके जिला प्रशासन या उसके नुमाइंदों पर इसका असर दिखाई नहीं दिया। जिसके फल स्वरूप जिले में कोरोना संक्रमित का एक मामला हम सबके सामने है।

हम ईश्वर से प्रार्थना करते है कि अब यह जिले में और ज्यादा अपने पैर न पसारे। लेकिन ईश्वर न करे और यह संक्रमण जिले में ज्यादा फैल जाए तो यह तय है कि जहांपना इसका ठीकरा जनता के सिर ही फोड़ेंगे। क्योंकि जहांपना यह तो मानेंगे ही नहीं कि गलती उनकी या उनके दरबारियों की ही है। खैर जो भी हो, लेकिन मुश्किलें जनता ही की बढ़ना है। कोरोना से यह जंग जनता को ही लड़ना है और जीतना भी है, तो आस-पास नजरे गढ़ाए रखे, संदेह होते सजग रहे, घर पर रहे सुरक्षित रहे।

भविष्य में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा मजदूर

माही की गूंज, झाबुआ।

इस सारांश का अर्थ मजदूरों के प्रति घृणा की उत्पन्न कर सकता है, किंतु लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती उभर कर सामने आनी वाली है। यह सिर्फ हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। परंतु सभी जगह अलग-अलग माहौल है, विकासशीलता के साथ अलग-अलग संसाधन, आर्थिक मोर्चे पर कार्य करने वाले लोग, वहां के राजनेता आदि है। अर्थव्यवस्था को संभालना काफी हद तक इन लोगों पर और इनकी कार्यशैली पर ही निर्भर करेगा। भारत के लिए मजदूर भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने की कगार पर है।

कोरोना ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा हैं, तो हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना जो छुआछूत से फैलने वाली महामारी बन चुका है, इसकी अभी तक कोई दवाई निर्मित नहीं हो पाई है। देश में फैर पसारती इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने सबसे बड़ा और कड़ा हथियार लॉकडाउन के रूप में उपयोग किया है। हालांकि लॉकडाउन का ही परिणाम है कि विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कोरोना भारत में अत्यंत धीमी गति से पैर फैला रहा है। पिछले कोई 40-45 दिन से लॉकडाउन जारी हैं, तो इससे होने वाली नुकसानी अथवा परेशानी भी देशवासी भुगत रहे है। देश का सबसे बड़ा वर्ग मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन लगते ही देशभर के उद्योग धंधे भी थम गए तो मजदूरों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। काम बंद होते ही बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपने घरों का रूख करना प्रारंभ कर दिया। मजदूरों की यह यात्रा हजारों किमी की होना थी, किंतु संसाधन कुछ भी नहीं थे। भूखे-मरने की मजबूरी ने मजदूरों को पैदल चलने पर विवश कर दिया, फिर भी भूख-प्यास सहित कई दुख-दर्दों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। देश की कई उद्योग नगरियों ने फैलती बीमारी के चलते इन्हीं मजदूरों को भगाना प्रारंभ कर दिया। जिनको कुछ समय पूर्व ही मिन्नतें कर बुलाया था। अचानक मजदूरों के प्रति इस दुर्व्यवहार ने मजदूरों की खुदराजी पर भी कड़ा प्रभाव छोड़ा तो पूरे देश में इन्ही मजदूरों की सुध सरकारों द्वारा न लेने से भी मजदूर आक्रोशित रहे। देश के कई हिस्सों में पैदल चलने वाले मजदूरों की मृत्यु तक हो गई, परंतु बीमारी के साये से जूझ रहे मजदूरों की सुध लेने में सरकारों ने विलंब कर दिया। मजदूरों पर राजनीति गर्माई तो सरकारों ने इनकी वापसी को समर्थन करना प्रारंभ कर दिया और प्रयास भी किए। फिर भी मजदूरों को लेकर सरकारों की स्थिति स्पष्ट नहीं रही। कुछ प्रदेशों की सरकार ने मजदूरों की वापसी का फैसला लेकर टाल दिया तो कइयों से वापसी के नाम पर मोटी रकम तक वसूली। उद्योग जगह से उपेक्षित मजदूरों सरकारों से भी संतुष्ट नहीं है। घर लौटने की सजा मजदूरों को रास्ते भर कहीं लूटपाट की सजा के रूप में मिली, कहीं उपहास के रूप में तो कहीं मृत्यु से भी सामना करा गई। यही टीस मजदूरों के मन में घर कर गई और कई मजदूर अपने घरों तक पहुंच भी गए।

घर पहुचे मजदूरों में अधिकांश का यही मत है कि घर-घर होता है अब मजदूरी करने परदेश का मुंह तक नहीं देखना है। घर पर रहकर कम पैसा कमा लेंगे किंतु विपरीत परिस्थितियों में मजदूरों को उपेक्षित करने की प्रवृत्ति से तो बचेंगे। कुछेक मजदूर वापसी की हिम्मत जुटाने की बात भी कर रहे है, किंतु मजदूरों का एक बड़ा तबका अब नहीं लौटने वाला। सरकारें प्रयास भी करें तो इस प्रयास में कई माह अथवा वर्ष लगने की संभावना अधिक है। मजदूरों पर अस्पष्ट सरकार से कई उद्योग जगह के लोगों ने भी मजदूरों की घर वापसी पर चिंता जताई है। उद्योगपतियों का कहना है कि यह मजदूर जो दर-दर की ठोकरें खाकर स्वयं के बल पर परेशानियों से सामना करते हुए घर पहुंच रहे है, इनका पुनः काम पर लौटना मुश्किल है। यही कारण है कि उद्योग जगत का लॉकडाउन के बाद भविष्य मुश्किलों भरा और लंबा होने वाला है। जिन समस्याओं से पूरे देश के मजदूर जूझ रहे है आने वाले समय में उससे भयानक स्थिति उद्योग धंधों और देश की अर्थव्यवस्था की होगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। जो मजदूर आज उपेक्षित है, परेशानियों से जूझ कर घर पहुंच रहा है, लॉकडाउन और कोरोना के बाद जल्द ही यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रतीत होगा।

संपादकीय

कोरोना योद्धाओं की जय-जयकार के साथ सेना का सलाम

इस बार सरहदें दो हैं और योद्धा भी दो किस्म के हैं। सरहदें भारत-पाकिस्तान के बीच की हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेखा की मर्यादा में आती हैं। इन सरहदों पर हमारे सशस्त्र सैनिक देश के दुश्मनों पर 'आंख' रखते हैं और घुसपैठिए आतंकियों से जूझते रहते हैं। ये रणबांकुरे हैं, तो देश आराम की नींद सोता है। सुरक्षित महसूस करता है। दूसरी सरहद अस्पतालों के भीतर और उनके गलियारों की है। वहां के योद्धा डॉक्टर, नर्सें और मेडिकल स्टाफवाला अन्य जुड़े कर्मवारी हैं। हमारे पुलिसवाले भी योद्धा से कमतर नहीं हैं। ये सभी योद्धा अपने-अपने मोर्चे पर एक हत्यारे, अदृश्य, अज्ञात वायरस-कोरोना-से लड़ रहे हैं। अपने घर-परिवार, सगे-संबंधी और निजी सरोकार बिल्कुल पीछे छूटे हैं। खुद के संक्रमित होने की चिंताएं भी नहीं हैं। बस, एक ही धुन सवार है कि देश के बीमार और संक्रमित नागरिक को एक बार फिर नई ज़िंदगी प्रदान करनी है। इन्हीं योद्धाओं की बदौलत ही देश के 11,700 से अधिक बीमार नागरिक नई सांसों और नई ऊर्जा के साथ स्वस्थ होकर अपने-अपने घर लौटे हैं। सशस्त्र और कोरोना योद्धाओं की 'जय-जयकार' करने और उनके भीतर नए मनोबल का संचार करने के मद्देनजर हमारी तीनों सेनाओं ने एक अनूठा प्रयोग किया। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइलों की प्रतिकृतियां और बंदरगाह, समुद्री जहाज आदि को देश के गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या सेनाओं के स्थापना दिवसों पर सजते हुए हम सबने देखा होगा। खूबसूरत रोशनियां की जाती हैं, मानो उस दिन भी दीवाली का पर्व हो! लेकिन सेनाएं आसमान से नागरिकों पर, अस्पताल और स्वास्थ्यकर्मियों पर फूलों की बरसात करें, सैन्य बैंड की परंपरागत धुनें बजा कर राष्ट्रीय उत्साह पैदा किया जाए, कमोबेश ऐसा प्रयोग अभूतपूर्व और अप्रत्याशित माना जा सकता है। देश ने यह भाव और मुद्रा पहली बार देखे हैं। हालांकि इस अभियान का खास फोकस कोरोना वायरस से लड़ने वाले 'योद्धाओं' को लेकर था, लेकिन उसी अंतराल में कश्मीर घाटी के हंदवाड़ा इलाके में, आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान, एक कर्नल, एक मेजर और दो जवानों, पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत पांच की शहादत की खबर आई, तो 'जय हो' के आयाम खोलने पड़े। हमारे जांबाज सैनिकों ने कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हैदर समेत दो आतंकियों को ढेर कर दिया और उनके ठिकाने को भी 'मलबा' बना दिया, लिहाजा 'योद्धाओं' के सम्मान का दायरा कुछ बढ़ाना जरूरी था। बहरहाल समूचे देश ने देखा होगा कि किस तरह सेना के हेलीकॉप्टर्स ने अस्पताल और उनके बाहर मौजूद 'योद्धाओं' पर पुष्प-वर्षा की थी। स्वास्थ्यकर्मियों ने हवा में अपने हाथ लहराते हुए सैनिकों का भी अभिनंदन स्वीकार किया। हमने टीवी चौनल्स पर असंख्य डॉक्टरों को तालियां बजाते और कुछ थिरकते हुए भी देखा। वे एहसास और सम्मान कैसे महसूस हुए होंगे? देश ने आसमान में गर्जना करते हुए लड़ाकू विमानों की 'गौरवमयी परेड' भी देखी होगी। बंदरगाहों और समुद्री पोतों को इस तरह रोशनियों से सजाया गया था कि पानी की सतह पर एक रोशन तख्ती चलती हुई लग रही थी। यह सम्मान-समारोह या आयोजन ही नहीं था, बल्कि भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर अपनी सशस्त्र शक्ति की नुमाइश की और अभ्यास भी किया। दरअसल जिस स्तर पर यह विचार तय किया गया, वह ही अभिनव था, लिहाजा उसे 'सरकस' करार देना अपमानजनक और निंदनीय महसूस हुआ। वामपंथी दलों ने इस अभियान के खर्च पर सवाल उठाए। दरअसल लोकतंत्र में ऐसी 'काली भेड़ें' भी मौजूद होती हैं, लिहाजा ऐसी टिप्पणियों की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। 'योद्धा' भी अपने बलिदान के सौदे नहीं किया करते, उनके सरोकार राष्ट्रीय होते हैं। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को रात-दिन जोखिम उठाकर काम करने की क्या जरूरत थी? वे भी 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते थे? आखिर कई डॉक्टर भी संक्रमित क्यों हुए? क्योंकि वे कोरोना रूपी सरहद पर तैनात थे। यही उनका राष्ट्रीय दायित्व था। उसे 'सरकस' के भाव में कैद करना बेहद शर्मनाक है। स्वास्थ्यकर्मियों ने तो पत्थरों के अलावा कई सामाजिक अपमान भी झेले हैं, लेकिन वे अपनी सरहदों पर तैनात रहे हैं। मानवता को बचाना उनका बुनियादी सरोकार और संस्कार है।

कोरोना के बाद बदल जाएगी दुनिया

कुलभूषण उपमन्यु
वरिष्ठ संभाषक

कोरोना महामारी ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आने वाले समय के बारे में कई सारे संशय खड़े दिख रहे हैं। वैश्विक संबंधों में नए ध्रुवीकरण सामने आने की दिशा के संकेत मिलने लगे हैं। एक ओर चीन के प्रति बढ़ते अविश्वास का दौर शुरू हो गया है तो दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं की कमजोरी का उजागर होना और यूरोपियन यूनियन के आपसी संबंधों में बिखराव के लक्षण दिखने लगे हैं। विश्व व्यापार संगठन की कारकरदगियों और उपयोगिता पर नए प्रश्नचिन्ह लगना भी स्वाभाविक हैं। विश्व समाज को यह समझ आने लगेगा कि स्थानीय अर्थतंत्र का सशक्त होना ऐसी आपदाकालीन परिस्थितियों में कितना जरूरी है। एक बार फिर गांधी के स्वावलंबी अर्थशास्त्र के चर्चा में आने और आशिक ही सही, प्रासंगिक बन जाने की संभावना है। विश्व एक गांव की अवधारणा की सीमाएं और खतरे भी उजागर होंगे। एक ओर सार्वजनिक उपक्रमों पर निर्भर अर्थतंत्र और दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं, दोनों ही प्रजातांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को कमजोर करने में रुचि रखती हैं। ये दोनों उत्पादन पद्धतियां एक खास तरह की तानाशाही और एकाधिकारवाद को बनाए रखने या प्रोत्साहित करने में अपना हित देखती हैं।

इस परिस्थिति में एक ओर जहां उत्पादन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव में उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार की खोज कमजोर होती है तो दूसरी ओर अनावश्यक उपभोक्तावाद, 'प्रयोग करो और फेंको' संस्कृति जैसी पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन को नष्ट करने वाली प्रक्रियाएं चल निकलती हैं, जिसमें हर कुछ बिकने-खरीदने की चीज बन जाता है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, पहाड़, जीव-जंतु और आदमी तक। लॉकडाउन में आदमी की गतिविधियों को विराम लगा तो गंगा निर्मल हो गई। जालंधर से धौलाधार की हिमाच्छादित चोटियां दिखाई देने लग पड़ीं। एक बात बड़ी स्पष्टता से समझ आने लगी कि आदमी के बिना प्रकृति तो बढ़िया फले-फूलेगी, पर प्रकृति के बिना आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। एक अदना सा वायरस जो हमारी ही प्रकृति विनाशक जीवन पद्धति की उपज होगा, पूरी दुनिया की रफ्तार को इस तरह विराम लगा देगा, किसने सोचा था। इस झटके के बाद कई बातों को नए सिरे से परिभाषित करना पड़े तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। बल्कि समझदारी इसी में है कि अहंकार छोड़ कर कुछ नया सोचें, प्रकृति मित्र जीवन पद्धति अपनाएं और उसी को मजबूत करने वाली उत्पादक और शासकीय पद्धतियों का विकास करें। ऐसा तभी संभव है यदि हम नम्रता से यह कबूल कर सकें कि हमने अंतिम सत्य के दर्शन नहीं किए हैं। इसलिए आगे नया सोचने, खोजने की अनंत संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि

विपत्ति के समय सबसे जरूरी वस्तु भोजन ही होता है। इसलिए भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यह सोच कर नहीं बैठ सकते कि जरूरत पड़ने पर आस-पड़ोस या दूसरे देशों से मंगवा लेंगे। इस परिस्थिति से दो-चार होने के लिए श्रम और प्रकृति के शोषण से बाहर निकलना होगा और ऑटोमेशन की तकनीकों को भी सीमित करना होगा। किंतु अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कोई एक देश इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकता है। देशों की सुरक्षा का ही मामला लें। दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिक और बड़ी मात्रा में आर्थिक संसाधन युद्ध विज्ञान की प्रगति की भेंट चढ़ रहे हैं। किंतु क्या कोई एक देश निःशस्त्रीकरण अपनी ओर से एकतरफा लागू कर सकता है? नहीं। जो जोर-शोर से निःशस्त्रीकरण की वकालत करते हैं, वही सबसे ज्यादा शस्त्र भंडार भी इकट्ठा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी कब्जा जमाए हुए हैं और वहां से भी कोई नई, बेहतर नियंत्रण विधि के विकास में बाधा बने रहते हैं। ऐसे में किसी अन्य देश से कैसे यह उम्मीद की जा सकती है कि वह इनके निःशस्त्रीकरण के उपदेशों को गंभीरता से ले।

असुरक्षा की भावना का बीजारोपण और उसके सहारे शांति की खोज का दिखावा कोरा भ्रम नहीं तो और क्या है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत से शांति तो नहीं सध सकती। क्या हम मनोवैज्ञानिक विकास के स्तर पर कबीलाई मानसिकता से बाहर निकलने में असमर्थ सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अब उत्पादक प्रक्रियाओं और व्यापार की व्यवस्थाओं को भी देखिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे विचार तो यह था कि दुनिया में खुला व्यापार हो और जहां जो वस्तु अच्छी और सस्ती तैयार हो सकती है, वहां वह तैयार हो और इससे अच्छी और सस्ती वस्तुओं का लाभ सारे विश्व को मिलेगा। किंतु उसका व्यावहारिक रूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सशक्त होते जाने, अपने आप में एक शासकीय इकाई की नीतियों को प्रभावित करने की भूमिका में प्रतिस्थापित हो जाने और एक नई तरह के एकाधिकार को जन्म देकर अन्य देशों के उत्पादक उपक्रमों को निगल कर और वैश्विक व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। उस पर सस्ते उत्पादन के लिए एक ओर प्राकृतिक कच्चे मालों का मूल्यांकन अन्यायपूर्ण तरीके से कम आंका जाता है, दूसरी ओर सस्ते श्रम की खोज और श्रम की जरूरतों को घटाने की क्षमता के विकास के लिए ऑटोमेशन को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसरों को समाप्त करते जाने का रास्ता पकड़ा गया है। जाहिर है कि विज्ञान की प्रगति के कारण मानव समाज को बेहतर जीवन प्रदान करने के जो हालात पैदा हो रहे हैं, उन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी आश्रयदाता सरकारों का वर्चस्व और कब्जा होता जा रहा है। ऊपर से यदि कोरोना जैसी कोई अलामत पैदा होती है तो वह अंतरराष्ट्रीय विकरालता ग्रहण कर ले रही है। हम विज्ञान में तो बहुत आगे जा गए हैं, किंतु व्यवस्थाओं के मामले में अभी भी वर्तमान की जरूरतों से काफी पीछे चल रहे हैं। युद्धक तैयारियों और व्यापारिक गलाकाट प्रतिस्पर्धाओं के बीच देश स्तर पर स्वावलंबी अर्थ व्यवस्थाओं की प्रासंगिकता और संयुक्त राष्ट्र संघ के सशक्त मानवतावादी संस्करण के विकास से संभव निःशस्त्रीकरण से ही कुछ ठंडी हवा के झोंकों की उम्मीद की जा सकती है।

झूठी श्रद्धा संदेह की जन्मदात्री है

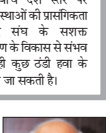

संदेह पैदा क्यों होता है दुनिया में? संदेह पैदा होता है झूठी श्रद्धा थोप देने के कारण। अपने छोटे बच्चे से तुम कहते हो मंदिर चलो। छोटा बच्चा पूछता है किसलिए? अभी में खेल रहा हूं। तुम कहते हो मंदिर में और ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन छोटे बच्चे को मंदिर में आनंद नहीं आता। तुम तो श्रद्धा सिखा रहे हो और बच्चा सोचता है यह कैसा आनंद है, यहां बड़े-बड़े लोग उदास बैठे हैं। यहां कोई खेल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, तो यह कैसा आनंद हुआ? फिर बाप कहता है, झुको, यह भगवान की मूर्ति है। बच्चा कहता है, भगवान! यहां तो पत्थर की मूर्ति को कपड़े पहना रखे हैं। बाप कहता है, झुको अभी, तुम छोटे हो, अभी तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। ध्यान रखना तुम सोचते हो तुम श्रद्धा पैदा कर रहे हो। वह बच्चा केवल सिर तो झुका लेगा, लेकिन उसे केवल मूर्ति पर संदेह आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि पर भी संदेह आ रहा है। अब वह सोचता है कि हमारा बाप भी कुठ मूढ़ है। कह नहीं सकता, कहेगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे। मां-बाप आगे चलकर परेशान होते हैं, वे कहते है क्या मामला है। बच्चे हमारे लिए श्रद्धा क्यों नहीं रखते? दरअसल, बच्चों का सरल हृदय तो टूट गया। उसके अंदर संदेह पैदा हो गया, झूठी श्रद्धा कभी संदेह से मुक्त नहीं हुई। वह तो संदेह की जन्मदात्री है। झूठी श्रद्धआ के पीछे आता है संदेह। जब मुझे पहली दफ़ मंदिर ले जाया गया और कहा गया कि झुको और मैंने कहा, मुझे झुका दो, क्योंकि मुझे झुकने जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं कहता हूं, मुझे अच्छे बड़े-बूढ़े मिले, मुझे झुकाया नहीं गया। कहा गया, जब तेरा मन करे तब झुकना, उसके कारण अब भी मेरे मन में अपने बड़े-बूढ़ों के प्रति श्रद्धा है। ख्याल रखना, श्रद्धा किसी पर जबरदस्ती मत थोपना, क्योंकि थोपने का प्रतिकार है संदेह। जिसका अपने मां-बाप पर भरोसा खो गया, उसका अस्तित्व पर भरोसा खो गया। श्रद्धा का बीज तुम्हारे झूठे संदेह के नीचे सूख गया।

मजदूरों की यात्रा पर राजनीति

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

भारत सरकार ने यह फैसला देर से किया लेकिन अच्छा किया कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलें चला दीं। यदि बसों की तरह रेलें भी गैर-सरकारी लोगों के हाथ में होतीं या राज्य सरकारों के हाथ में होतीं वे उन्हें कब की चला देते। करोड़ों मजदूरों की घर-वापसी हो जाती और अबतक काम पर लौटने की उनकी इच्छा भी बलवती हो जाती लेकिन अब जबकि रेलें चल रही हैं, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक नजारा देखने को मिल रहा है। जिन मजदूरों की जेबें खाली हैं, उनसे रेल-किराया मांगा जा रहा है और एक वक्त के खाने के 50 रु. ऊपर से उन्हें भरने पड़ रहे हैं। इसके विपरीत विदेशों से जिन लोगों को लाया गया है, उनको मुफ्त की हवाई-यात्रा, मुफ्त का खाना और भारत पहुंचने पर मुफ्त में रहने की सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। यह अच्छी बात है लेकिन ये लोग कौन हैं? ये वे प्रवासी भारतीय हैं, जो विदेशों में काम करके पर्याप्त पैसा कमाते हैं लेकिन इनके मुकाबले हमारे नंगे-भूखे मजदूरों से सरकार रेल-किराया वसूल कर रही है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? खास तौर से तब जबकि श्रंप्रधानमंत्री परवाह करते हैंश्र (पीएम केयर्स फंड) में सैकड़ों करोड़ रु. जमा हो रहे हैं।

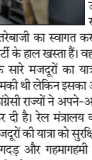

प्रधानमंत्री किसकी परवाह कर रहे हैं? अपने जैसे लोगों की? खाए, पीए, धाए लोगों की? जो भूखे-प्यासे गरीब लोग हैं, उनकी परवाह कौन करेगा? यदि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन वंचितों के लिए आवाज उठाई तो इसमें उन्होंने गलत क्या किया? यदि इसे आप राजनीतिक पैंतरेबाजी कहते हैं तो मैं इस पैंतरेबाजी का स्वागत करता हूं। हालांकि सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के हाल खस्ता हैं। वह सोनिया के इस दावे पर अमल कैसे करेगी कि सारे मजदूरों का यात्रा-खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। यह कोरी धमकी थी लेकिन इसका असर अच्छा हुआ है। कई कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी राज्यों ने अपने-अपने यात्रियों का खर्च खुद करने की घोषणा कर दी है। रेल मंत्रालय को अब यही देखना है कि वह इन करोड़ों मजदूरों की यात्रा को सुरक्षित ढंग से संपन्न करवा दे। यदि यात्रा की इस भगदड़ और गहमागहमी में कोरोना फैल गया तो देश के सामने मुसीबतों का नया पहाड़ उठ खड़ा होगा।

(लेखक सुप्रसिद्ध पत्रकार और स्तंभकार हैं।)

अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी

अपने देश में लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलते ही कई जगह कल दिशा-निर्देशों की जिस तरह अवहेलना हुई, वह न केवल दुखद, बल्कि शर्मनाक भी है। केंद्र और राज्य सरकारों ने एक योजना के तहत सोच-समझकर ढील दी है। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद कुछ क्षेत्रों में ढील देना आवश्यक हो गया था। समाज और अर्थव्यवस्था की ओर से मांग उठ रही थी। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की व्यवस्था की। अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही पूरी पाबंदियां लागू हैं, तो यह जरूरी भी है, लेकिन बाकी जोन में समाज की जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा रियायत दे दी गई है। दी गई रियायत के लिए लोगों को शासन-प्रशासन का आभारी होना चाहिए। ध्यान रहे, हम मिली हुई रियायत का सम्मान नहीं करेंगे, तो वह छिन जाएगी, जैसे अनेक राज्यों में पहले ही दिन छिन गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे अपेक्षाकृत पढ़े-लिखे क्षेत्र में भी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते दिखे, यह किसी अपराध से कम नहीं है।

खासकर आबकारी विभाग की दुकानों के आसपास जिस तरह की भीड़ देखी गई है, वह किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय है। कई जगह पुलिस को बल प्रयोग के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुछ शहरों और राज्यों में दी गई रियायत को वापस भी ले लिया गया है। सरकार ऐसे इलाकों में फिर कड़ाई के लिए मजबूर हुई है और लोगों की मांग पूरी करने के दूसरे रास्ते खोजने को विवश है। कुछ लोग पुलिस या सरकारों को भी दोषी ठहराएंगे, पर कुल मिलाकर यह समय संतुलित चिंतन और समझदारी का है। समाज में एक बड़ा हिस्सा है, जो लॉकडाउन को गलत ठहरा रहा है, तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है, जो लॉकडाउन में ढील देख रहा है। सबसे ज्यादा उदास करती चिंता उस हिस्से को लेकर है, जो बार-बार साबित कर रहा है कि उसे फिजिकल डिस्टेंसिंग की खास परवाह नहीं है, उसे केवल पुलिस के डंडे या कानूनी कार्रवाई की भाषा समझ में आती है। ये लापरवाह लोग खुद अपने ही नहीं, समाज के भी दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी बार-बार कह रहे हैं कि हमें कोरोना से बचकर जीना सीखना होगा, कम से कम कोविड-19 की दवा मिलने तक तो जीने की यही अनिवार्य शर्त है।

यह समय है, जब हमें स्व-नियमन सिखना होगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं दीप बनो। किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि स्वयं को नुकसान पहुंचाओ। हम आखिर क्यों ऐसी नौबत लाते हैं कि सरकार ज्यादती करे और पुलिस लाठी उठाए। एक सभ्य, जागरूक, लोकतांत्रिक समाज को स्वयं अपना नियमन और संचालन करना चाहिए। विशेष रूप से जब आपदा आन पड़ी हो, तब तो हमें समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, समस्या की वजह नहीं। आज हम पर मूलभूत पाबंदी यही है कि हम भीड़ में न जाएं, परस्पर सुरक्षित दूरी रखें। ध्यान रहे, स्व-नियमन और स्व-सतर्कता में बड़ी ताकत होती है। हम अगर दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाएंगे, तो पुलिस भला हमें कब तक बचाएगी? ठीक से समझ लेना चाहिए, अगर एक-एक आदमी यह ठान ले कि वह किसी भी सूरत में फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना करेगा, सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा, तो कड़े लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सारे देश को ग्रीन जोन बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

काश! पुलिस की यही छवि रह जाए

विष्णुदेव नारायण राय
पूर्व आईपीएस अधिकारी

कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद दुनिया वही नहीं रहेगी, जो उसके पहले थी। तमाम समाजशास्त्री अपनी-अपनी समझ के मुताबिक आने वाले फर्क को रेखांकित कर रहे हैं। सभी इस पर तो सहमत हैं कि हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, पर आने वाला कल कैसा होगा, इस पर आम राय नहीं बन पा रही। भारतीय संदर्भ में भी एक सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है और यह इसलिए भी दिलचस्प है कि बदलाव एक ऐसे संगठन की छवि में हो रहा है, जो दुर्भाग्य से अपने गठन के बाद से ही नकारात्मक छवि की समस्या से जूझता रहा है। यह संगठन भारतीय पुलिस है, जो एक आधुनिक संस्था के रूप में 1860 के दशक में अस्तित्व में आया था।

1857 के विद्रोह को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी और उसका मुख्य उद्देश्य अपने गौरांग महाप्रभुओं के शासन को सुदीर्घ और सुदृढ़ करना था। काफी हद तक अपने उद्देश्यों में यह सफल भी रही, पर शासकों के लिए कुछ भी करने को तत्पर इस संस्था की छवि जनता के मित्र जैसी कभी नहीं बन सकी। यद्यपि एक लोकतांत्रिक गणतंत्र में यह अजीब लगेगा, पर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि भारतीय जनता और पुलिस के आपसी रिश्ते शत्रुवत अधिक रहे। आजादी के बाद स्थिति बदलनी चाहिए थी, पर शायद हमारे नए शासकों को भी ऐसी ही पुलिस भाती थी, जो जनता की सेवक से अधिक उनकी चाकर हो, इसलिए उन्होंने पुलिस के चरित्र में कोई बुनियादी परिवर्तन करने से गुरेज किया। इस पर लंबा अकादमिक विमर्श हो सकता है कि तमाम आयोगों की सिफारिशों और अदालती निर्णयों के बावजूद क्यों भारतीय पुलिस की मानसिकता लगभग वैसी ही बनी हुई है, जैसी शैशवावस्था में विकसित हुई थी?

इस पृष्ठभूमि में कोरोना के दौरान भारतीय पुलिस के व्यवहार में आए परिवर्तन आपको चकित कर सकते हैं। अचानक अखबारों या सोशल मीडिया में ऐसी काफी खबरें पढ़ने को मिलने लगी हैं या ऐसी तस्वीरें दिखने लगी हैं, जिनसे पुलिस को लेकर हमारी पारंपरिक समझ गड्ड-मड्ड हो गई है। नोएडा के एक चिंतित पति को उसकी पत्नी की प्रसूति के ठीक पहले बरेली पहुंचाना हो, अपने जन्मदिन पर उदास बैठे बच्चे तक केक पहुंचाकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौटाना हो, शाहजहांपुर के एक गांव में कैंसर के मरीज को दिल्ली से दवा उपलब्ध करानी हो या किसी असहाय परिवार को कई दिनों बाद पहला भोजन कराना हो- सब कुछ ऐसा लगता है, जैसे हम किसी दूसरे ग्रह की पुलिस के बारे में देख-पढ़ रहे हैं। कोरोना योद्धाओं की सूची में डॉक्टरों और पैरा मेडिक्स के साथ पुलिस भी सम्मिलित हो गई है। पहली कतार के योद्धाओं में उसका भी जिक्र हो रहा है। अन्य लड़ाका बलों के बीच उसकी कुर्बानियां कम उल्लेखनीय नहीं हैं। अब तक लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में शहादत दे चुके हैं और सौ से अधिक ड्यूटी देते हुए संक्रमित होकर अस्पतालों में भरती हैं। पंजाब पुलिस के एक एएसआई के कानून तोड़ने वालों से बहादुरी से भिड़ जाने और अपना हाथ कटवा लेने के दृश्य तो वर्षों तक राष्ट्रीय स्मृति में अंकित रहने वाले हैं।

पहली बार पुलिसकर्मियों की सेवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शिनाख्त हुई है। 3 मई को जो हुआ, वह तो अभूतपूर्व था। दिल्ली के पुलिस स्मृति स्थल पर तीनों सेनाध्यक्षों ने पहली बार एक साथ जाकर शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति को नमन किया। देश भर में लोगों ने ड्यूटी पर खड़े पुलिसकर्मियों को फूल-मालाएं पहनाईं। कोविड-19 की लड़ाई में अस्पतालों के साथ पुलिस थानों के योगदान को भी स्वीकार किया गया। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों के योगदान को रेखांकित करने के लिए तालियां बजाने या दीया जलाने की अपील की थी, उनमें पुलिसकर्मी भी थे।

इस बार की तालियां या फूल उस हैदराबादी प्रशंसा से भिन्न थे, जो कुछ ही महीनों पूर्व बलात्कारियों को 'मुठभेड़' में मार डालने पर तेलंगाना पुलिस को मिली थी। तब शुरुआती उत्साह के बाद जल्द ही सन्नाटा खिंच गया, क्योंकि जनता को एहसास हो गया था कि वह कोई सच्ची मुठभेड़ नहीं थी, और पुलिस को इसकी इजाजत देने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। हिंसा के सामाजिक समर्थन की प्रवृत्ति भारतीय मानस में कहीं न कहीं गहरे पैठी हुई है, जो हैदराबाद में दिखी और इस कोरोना-संकट में भी बीच-बीच में दिखती रहती है। अक्सर मना करने के बावजूद सड़क पर निकल पड़ने वालों को लठियाते, उठक-बैठक कराते या कान पकड़कर दौड़ाते पुलिसकर्मियों को देखकर लोग या तो उनके कृत्य का समर्थन या अपना मनोरंजन करते हैं। यह कानून का उल्लंघन करने वालों को गैर-कानूनी सजा देने वाली स्थिति है, जिसका अक्सर हम समर्थन करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि यही प्रवृत्ति आगे चलकर हिरासती हत्या या हाथ-पैर तोड़ने जैसी बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है। इन सबके बावजूद इस बार जन-समर्थन किसी नकारात्मक कारण से नहीं, बल्कि परिवार के सुखद माहौल से दूर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना रात-दिन कर्तव्यरत पुलिसकर्मियों की प्रशंसा में है।

यह महत्वपूर्ण है कि इस महासंकट में उस संस्था की याद भारतीय जनता को आई, जिससे रोज उठते-बैठते उसका साक्षात होता रहता है। हमें उसकी याद हमेशा गलत कारणों से आती है, मगर इस बार सकारात्मक कारणों से उस पर हमारा ध्यान गया। यह उनका हक था और देश ने भरपूर उनकी पीठ थपथपाई भी। देखना यह है कि क्या यह परिवर्तन संस्थाबद्ध हो पाएगा? ऐसा तो नहीं कि जब स्थिति सामान्य हो जाए, तो पुलिस वापस अपनी चाल पर लौट आए? इतना तो निश्चित है कि जिंदगी पटरी पर लौटने के बाद सरकार इन दिनों के अनुभवों से सबक लेकर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन करेगी। क्या उसे पुलिस में व्यापक सुधार करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? यह काम 1947 से लंबित है और आजाद भारत की पुलिस भी जन-विरोधी बनी हुई है। तमाम आयोगों की अनुशंसाएं दफ्तरों में धूल चाट रही हैं।

कोरोना-काल ने कुछ छवियां पेश की हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता की मित्र पुलिस कैसी होगी? जरूरत सिर्फदो हैं। पहली यह कि शासकों की समझ में यह बात आनी चाहिए कि जनता की मित्र पुलिस जरूरी नहीं कि उनके हितों के खिलाफही हो और दूसरी, जनता को भी समझना होगा कि लोकतंत्र का अंग होने के कारण यह उसका अधिकार है कि उसे एक सभ्य पुलिस मिले, और यदि इस बार उसने पुलिस के अच्छे काम को रेखांकित किया है, तो भविष्य में जरूरत पड़ने पर वह इसके लिए आंदोलन भी कर सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

चाणक्य नीति

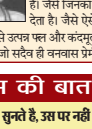

किसी भी कार्य को करने से पहले देख लेना चाहिए कि उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। यदि प्राप्त लाभ से बहुत अधिक परिश्रम करना पड़े तो ऐसे परिश्रम को न करना ही अच्छा है। माला गूंथने से, चंदन घिसने से या ईश्वर की स्तुति का स्वयं गान करने से ही किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो जाता है। जैसे जिनका यह व्यवसाय है उन्हें ही वैसा करना शोभा देता है। जैसे ऐसे ब्राह्मण को महापुरूष कहा जाता है, जो उस भूमि से उत्पन्न फल और कंदमूल खाकर जीवन-यापन करता है। जो जोती न गई हो, जो सदैव ही वनवास प्रेमी हो और जो नित्य ही श्रद्धावान हो।

काम की बात

आप जो सुनते है, उस पर नहीं बल्कि जो अनुभव करते है, उस पर विश्वास करें।

एक सलाह

पीठ पीछे किसी की बुराई करना अपने ही अपराधी होने की पुष्टि करता है।

शराब से ज्यादा देश जरूरी

सिद्धार्थ शंकर

लॉकडाउन नए सिरे से लागू होने के साथ ही देशभर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से नई व्यवस्था लागू हो गई। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब दुकान खोलने की अनुमति गई है। इसके बाद सुबह से ही इन दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें देखी गईं। कर्नाटक से लेकर दिलली, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीरें आई हैं। दिल्ली में कई किमी लंबी लाइनें नजर आईं। यहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकानें भी सोमवार से खुल गईं। बीते करीब डेढ़ महीने से घरों में कैद लोग अपनी कटिंग और शेविंग बनवाने पहुंच रहे हैं। हालांकि सभी दूर फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी का पालन हो रहा है और लोग मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। जहां-जहां भारी अव्यवस्था नजर आई, वहां सवाल उठाए जा रहे हैं कि महामारी रोकना जरूरी है या शराब दुकानें खोलना। हालांकि, शराब की दुकानें खुलने पर कई राज्यों में सारे नियम ताक में रख दिए गए। शारीरिक दूरी के नियमों की परवाह किए बगैर लोग शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ के रूप में जमा हो गए। देश में लॉकडाउन का तीसरा दौर ऐसे समय शुरू हुआ है, जब कहा जा रहा है कि देश के सामने करो या मरो वाली स्थिति है। संक्रमण काबू में है जरूर, मगर किसी भी समय अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। दारू के प्यासे लोगों का उतावलापन जिस तरह से दिखा, वह सही नहीं है। कुछ लोगों की दारू के चक्कर में कहीं पूरा देश दवा पर न निर्भर हो जाए। सरकार ने हालांकि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, तो कुछ सोचा भी होगा, मगर एक उपाय अमल में लाया जाता तो काफी बेहतर रहता। यह है-होम डिलेवरी। इस सुविधा के साथ शराब की दुकानें खोली जातीं तो लॉकडाउन का पालन भी हो जाता, लोगों की इच्छा भी पूरी हो जाती और सरकार की कमाई भी होती। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, वह खतरे में डालने वाली है। इस पर सरकार को गौर करना होगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन

खत्म होते ही हम कोरोना के खतरे से मुक्त हो जाएंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। लॉकडाउन का वक्त हमें यह बता रहा है कि अब हम ज्यादा सतर्कता बरतें और जिम्मेदार नागरिक बनें। ऐसा इसलिए भी है कि कोरोना ही नहीं, दूसरी संक्रामक बीमारियां भी कम बड़ा खतरा नहीं हैं। लोगों को यह समझना होगा कि लॉकडाउन जैसा कदम कोई सजा नहीं है, बल्कि खुद उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया सबसे जरूरी कदम है। आज इटली, स्पेन और अन्य यूरोपीय देश व अमेरिका जिस भयावह दौर से गुजर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी लापरवाही लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लेना ही रही है। हम इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं फिर भी खुद को और दूसरों को जोखिम में डाल रहे हैं। शराब का एक घूंट पूरे देश को लडखड़ाने पर मजबूर कर दे, यह गलत होगा।

लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था को तकरीबन बारह लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का जो अनुमान व्यक्त किया गया है, वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। लेकिन देश इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसमें सबसे प्रथमिकता लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने की है। इसलिए इस भारी-भरकम नुकसान को झेलने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। कोरोना विषाणु को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनिया भर के देशों को जो पहला परामर्श जारी किया था, वह लॉकडाउन का ही था। लॉकडाउन एक बेहद कठोर कदम है, लेकिन अपरिहार्य भी है। अगर भारत ने लॉकडाउन नहीं किया होता, तो आज तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह होती। लेकिन अब शराब के मतवाले अब तक की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं।

तस्वीर की त्रासदी, त्रासदी की तस्वीर

अवधेश बजाज, लेखक

यह असह्य छटपटाहट निश्चित ही अमरता का अभिशाप ढो रही है। मैं भी अभिशाप हो गया हूँ, इस द्वापर का लोन जख्म की भांति अपने कपाल पर सहन करने के लिए। अकेला मैं ही क्यों, हमारे सम-हृदयी संकुल की विचार श्रृंखलाओं वाली वीथिकाओं में रक्से - बिस्मिल चरम पर है। हम अश्वत्थामा नहीं, किन्तु हमारे कपाल पर एक मणि के होने का गुमान हमेशा से चस्या कर दिया गया था। वह पत्थर इन बेशकीमती ख्यालों से चमकता-दमकता था कि हम मानव समाज में रह रहे हैं। इस मणि के स्पर्श से ही हमारी मस्तिष्क पटल पर यह चलचित्र खिंचा हुआ था कि सचमुच हम श्नारी तुम केवल श्रद्धा हो...श् वाली पंक्तियों के व्यावहारिक पक्ष वाले धरातल पर श्वांस ले रहे हैं। किन्तु हाल ही में वह मणि जैसे किसी ने उखाड़ फेंकी। कपाल के नीचे टकी दो आँखों ने यह छायाचित्र देख लिया। कानों ने वह सुनने का दंड सिर-माथे उठा लिया, जो मस्तिष्क के सुन्न होने की प्रक्रिया को नामालूम स्तर तक वाली पीड़ा की और सतत रूप से धकेलता जा रहा है। क्योंकि यह उस अभागी माँ का मामला है, जो देशव्यापी तानाशाही की जंजीरों को एक हजार दो सौ अँठ्यावन किलोमीटर वाले फसले तक के लिए सहने को विवश कर दी गयी है। दुधमुँही बच्ची को गोद में लिए उसे गुजरात के सूरत से उत्तरप्रदेश के प्रयागराज तक पैदल ही यह सफ़र तय करना है। मानव निर्मित हालात की आग और प्रकृति निर्मित मौसम की आँच के बीच वह एक साथ अनेक किरदार जी रही है। उस स्त्री का, जो इस देश की वर्तमान शासन व्यवस्था में श्गरीबश् और श्अमश् होने की सजा इस रूप में भुगत रही है। उस माँ का, जो अपने कलेजे के टुकड़े की कलेजा मुंह को ला देने वाली हालत देखने के बावजूद लाचार है। वह रबीन्द्रनाथ ठाकुर की य... एकला चलोश् वाली प्रेरणा नहीं है, अपितु निराला की श्...देखा मैंने उसे इलाहबाद के पथ परश् वाली ऐसी त्रासदी है, जो अब पत्थर नहीं तोड़ रही. बल्कि वह पत्थर बना दिए गए हालात को तराशती हुई उन्हें जिंदगी का स्वरुप देने की लगातार नाकाम होती कोशिश कर रही है। कहने को तो वह कोरोना वायरस से खुद और बच्ची की हिफ़ाजत के लिए इस दुर्गम सफ़र पर निकली है, किन्तु यह अर्द्ध सत्य का ही साक्षात्कार है. क्योंकि शरीर-भर से फूटा पसीने का झरना तो कोरोना के

विषाणु को अपने नमक में घोलकर खत्म कर देने की ताब रखता है। जिस्म के भीतर चल रहा भावनाओं का सैलाब कोविड-19 को अतल गहराइयों के भीतर तक गर्क करने में पूर्णतः सक्षम है। वह दरअसल उस शोक यात्रा पर निकली है, जो देश की सत्ता के कर्णधारों की शौक यात्रा की पाशविक प्रवृत्ति की वजह से उसे आरम्भ करनी पड़ी है। सारा मुल्क कोरोना के शोक में डूबा है और हुक्मरानों को शौक है कि इसका भी अपनी तरह से जश्न मना लिया जाए। कोरोना की रोकथाम के नाम पर एक बार फिर विभाजन सदृश हालात बनाकर, नोटबंदी की तरह ही पुनः यकायक बंदिशें लादकर, बीते करीब साढ़े छः वर्ष की भांति तमाम तानाशाही निर्णयों को देश की जरूरत का नाम देकर। तो केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी और उनके हरकारे जो कोरोना पर्व फ्लिहाल मनाने में मशगूल हैं, यह महिला और उसकी बच्ची उसी उत्सव का हृदयविदारक काला सत्य हैं। यह छायाचित्र उस शासन व्यवस्था की प्रेत छाया का प्रतिबिम्ब है, जो जन-आकांक्षाओं की लाश के साथ मनमाने एवं जन-विरोधी फैसलों वाली कपाल क्रिया करने में अघोरियों के समूह की तरह जुटी हुई है। लोक तंत्र के गीत के नाम पर इस पवित्र भावना का मर्सिया पढ़ने का जो निर्वसन चरित्र इस मुल्क की व्यवस्थाओं पर हावी है, वह ही श्क्लिकश् के आत्मा को दहला देने वाले उस स्वर को गूंजने का निमित्त बनता है, जो क्लिक ऐसे छायाचित्र को हमारे सामने ले आता है। और हम पथराई आँखों से वह देखने को विवश हो जाते हैं, जिस विवशता की पीड़ा को मैं यह छाया चित्र देखने के बाद से लगातार भोग रहा हूँ।

किसी वीर पुरुष की कहानी पढ़ी थी। अपने हाथ में हुए खतरनाक घाव का दर्द बिसरने के लिए वह शरीर के अन्य हिस्से को उसी भी बड़ा घाव दे देता है। ताकि अपेक्षाकृत छोटे दर्द की पीड़ा को कम महसूस किया जा सके। इस महिला की दशा से उपजी व्यथा की लकीर को छोटा करने के लिए मैं उसके बरअक्स अमरकांत के श्दोपहर का भोजनश् वाली सिद्धेश्वरी की भूख को याद करता रहा। मैंने मैक्सिम गोर्की की श्माँश् यानी पेलगाया निकोवना वसोवा की औलाद के लिए संघर्षमयी जीवन यात्रा का पूरी शिद्दत से स्मरण किया। रूथ वाटरमैन की भोपाल स्मारक वाली बच्चे को गोद में लेकर विलाप करती माँ की प्रतिमा में प्राण फूंकने का जतन किया। सत्यजीत रे की श्अपराजितेश् के दर्द को स्वयं में कायांतरित करने प्रयास किया। यह सब इसलिए कि इन सभी तकलीफ़ों के आगे सूरत से प्रयागराज तक पैदल सफ़र को विवश इस माँ की पीड़ा की अपने भीतर से व्यथा को कुछ कमतर आंक सकूं। किन्तु मानव द्वारा रचे गए इन चरित्रों के आगे सत्ताधीश दानव की करतूत के रूप में सामने आये इस चरित्र को कोई भी परास्त नहीं कर सका। इस तस्वीर का दर्द न जाने कितने समय तक मुझे निरंतर सालता रहेगा।

'साकेत' में लिखा गया है-
जिसने मम यातना सही,
यह पार्श्वस्थ सुलक्षणा वही।
यह भी उस काल थी खली,
मुझको जो घर संग ले चली।'

त्रेतायुगीन उर्मिला और बहुत बाद वाले और के मैथिलीशरण गुप्त, दोनों ही अतीत का विषय बन चुके हैं। किन्तु श्साकेतश् की यह पंक्तियाँ सूरत से प्रयागराज के बीच क्या किसी कोरोना गाथा की भांति हमेशा सिहरन का विषाणु संचारित नहीं करती रहेंगी! वह गाथा, जो सरकारी बदइंतजामी, हृदयहीनता वाले निर्णयों तथा बीते साढ़े छह साल की अनंत मनमानियों की परिणती है।

कोरोना मुक्ति की राह पर सरकार, संगठन और समाज का समन्वित सफर

विष्णुदत्त शर्मा

प्रदेश में शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने या यूं कहें इस प्रदेश को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार से मुक्त हुए लगभग एक महीना पूरा हुआ है। इतना समय किसी सरकार के कामकाज, उसकी उपलब्धियों के आंकलन के लिए पर्याप्त नहीं होता। लेकिन भाजपा की इस सरकार के ये 30 दिन कई मायनों में अनूठे रहे हैं। इन 30 दिनों में सरकार, पार्टी संगठन और समाज ने कोरोना महामारी के खिलाफलड़ाई में आपसी समन्वय का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह अद्वितीय है। सरकार ने बिना समय गवांए कमांडो शैली में कार्रवाई की, तो समाज पूरी उदारता के साथ प्रभावितों, जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ितों की मदद के लिए नियोजित प्रयास किए। इन सम्मिलित प्रयासों ने न सिर्फ कोरोना महामारी के बढ़ते कदमों को थाम लिया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती से मुकाबले के लिए यह एक कारगर रणनीति हो सकती है।

शून्य से शुरू हुआ सरकार का काम

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने जब कार्यभार ग्रहण किया, तो देखा कि प्रदेश में इस महामारी से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई थी, कोई आधारभूत सुविधाएं नहीं जुटाई गई थीं और न ही इस संकट से मुकाबले के लिए कोई तंत्र था। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि काम शुरू कहां से किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार ने अभूतपूर्व तेजी और चुस्ती के साथ कमांडो शैली में काम करना शुरू किया। आनन-फानन में 450 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर कंट्रोल रूम शुरू किया गया, वहीं राज्य स्तर पर अधिकारियों की कोर टीम बनाई गई। शिवराज सरकार ने अस्पताल, आईसीयू बेड जुटाने से लेकर मास्क, सैनिटाइजर, टेस्ट किट और ईपीई किट तक जुटाने का काम शुरू किया। कोरोना टेस्टिंग के लिए प्रदेश में ही सुविधाएं जुटाई गईं। अब प्रदेश में ही रोजाना 10 हजार से अधिक ईपीई किट बनाई जा रही हैं, जिससे चिकित्सा और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध हो सकी है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफलड़ाई में किस तेजी से काम किया है, उसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक माह से भी कम समय में प्रदेश में कोरोना टेस्ट करने वाली लैबों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। प्रदेश में 20,243 आइसोलेशन बेड तथा 783 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा 690 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं तथा प्रदेश में 23 अस्पताल सिर्फकोरोना के उपचार के लिए ही निर्धारित किए जा चुके हैं। चौहान की सरकार ने एक तरफये सुविधाएं जुटाकर कोरोना महामारी पर सीधा प्रहार किया, तो

दूसरी तरफ गरीबों, निराश्रितों, श्रमिकों, किसानों और आदिवासियों के लिए विशेष उपायों की घोषणा करके इन वर्गों को इस लड़ाई के अप्रत्यक्ष परिणामों से सुरक्षा दी।

उदारता से आगे आया समाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीते 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को उम्मीदों से अधिक सफल बनाकर समाज ने यह जता दिया था कि वह न सिर्फप्रधानमंत्री जी की भावनाओं को समझ रहा है, बल्कि इस लड़ाई में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को भी तैयार है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान आ रही मुश्किलों को झेलते हुए भी हमारा समाज उसे सफल बनाने में जुटा हुआ है। यही नहीं बल्कि समाज ने इस लड़ाई में पीड़ितों और जरूरतमंदों की सहायता के काम में भी काफी उदारता दिखाई है। पीड़ितों की मदद करने के प्रधानमंत्री के आह्वान ने किस गहराई तक लोगों को छुआ, इसका अनुमान उन बच्चों के त्याग से लगाया जा सकता है, जिन्होंने पीएम केअर पंद्ध में दान देने के लिए अपनी गुल्लक तोड़ दी या साइकल खरीदने के लिए एक-एक रुपया करके जोड़े हुए पैसे दान कर दिये। बड़ी संख्या में आगे आए सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने सिर्फपीएम केअर पंद्ध और मुख्यमंत्री सहायता कोष में उदारतापूर्वक दान ही नहीं दिया, बल्कि ये जरूरतमंद लोगों को भोजन और राशन उपलब्ध कराने में भी पीछे नहीं रहे।

पार्टी संगठन ने निभाई सामाजिक जिम्मेदारी

कोरोना महामारी से मुकाबले के बीते तीस दिनों में एक तरफ जहां प्रदेश सरकार ने इस महामारी पर सीधे प्रहार किये तो, पार्टी के करीब 05 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज पार्टी संगठन द्वारा तैयार की गई एक सुविचारित रणनीति के तहत इस महामारी के दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए काम करती रही। चाहे घर लौट रहे प्रवासी मजदूर हों, बेसहारा बुंजुर्ग हों या जरूरतमंद गरीब परिवार, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर किसी की मदद की। केंद्रीय नेतृत्व की मंशा को ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाज के सहयोग से कम्युनिटी किचन स्थापित किए, ताकि कोई भूखा न सोए। कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में भोजन तैयार कराकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया और पार्टी कार्यकर्ता अब तक लगभग 01 करोड़ 10 लाख भोजन पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचा चुके हैं। शासन और प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, आवास और चिकित्सा की व्यवस्था की। गरीब बस्तियों में जाकर 60 लाख से अधिक मास्क और सैनिटाइजर बांटे, तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व भी बताया। जरूरतमंद परिवारों के बीच पार्टी कार्यकर्ता अब तक 14 लाख, 43 हजार राशन किट वितरित कर चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम किया कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए संसाधन जुटाने का। पार्टी के 02 लाख 74 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने स्वयं तो पीएम केअर पंद्ध में दान दिया ही है, उन्होंने अपने सामाजिक नेटवर्क के जरिए लगभग 08 लाख, 81 हजार लोगों को भी इस पंद्ध में दान देने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व द्वारा प्रदेश के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल हैं। टास्क फोर्स के सदस्य सरकार और जनता के लगातार संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री के साथ टास्क फोर्स की नियमित रूप से बैठक हो रही है, जिसमें टास्क फोर्स के सदस्य उन्हें फीडबैक देते हैं। कुल मिलाकर बीते एक महीने में पार्टी संगठन ने जहां एक कुशल योजनाकार की भूमिका निभाई, तो कार्यकर्ताओं ने अपने आचरण से यह बता दिया कि देश और समाज के प्रति जिम्मेदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए।

(लेखक मप्र भाजपा के अध्यक्ष और सांसद हैं।)

आंकड़े और उनके प्रचार-प्रसार में इस सरकार का कोई सानी नहीं

इतिहास साक्षी है कि अनजाने में हुई मानवीय भूलों के नतीजे भयंकर होते हैं। कोई सोचे कि यदि राम को सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास न हुआ होता या सीता मायावी रावण के प्रलोभन में लक्ष्मण रेखा न लांघती, तो लंका और रावण के खानदान का (विभीषण के अलावा) विनाश कैसे होता? यदि शकुनि की चाल में फंसकर युधिष्ठिर राजपाट और द्रोपदी को गंवाकर हर प्रकार से चौपट न हुए होते, तो क्या महाभारत का विध्वंस संभव था?

यदि भारत सरकार समय रहते समुचित कदम न उठाती , तो क्या कोरोना से प्रभावी तरीके से जूढना मुमकिन होता? फिर भारत के प्रगतिशील बुद्धिजीवी कैसे अफ्सोस जताते कि यदि और टेस्ट होते, तो परिणाम अधिक वास्तविक आते। जैसे वे सब दुखी हैं कि भारत ने संक्रमण रोगियों का विश्व कीर्तिमान क्यों नहीं बनाया। वह भी लाइलाज मर्ज से पीड़ित इतने लोगों का अस्पताल पहुंचना और फिर सकुशल घर लौट आना।

एक निराश बुद्धिजीवी दिल का दर्द कुछ यूं बयां करते हैं और किसी क्षेत्र में हो न हो, आंकड़े और उनके प्रचार-प्रसार में इस सरकार की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। पहले तो परिवार तंत्र को ही प्रजातंत्र का पर्याय समझ लिया जाता था। अब इन निष्ठावान बुद्धिजीवियों को कोई कैसे समझाए कि भारत आज पारिवारिक एकतंत्र न होकर संसार का विशाल और गतिशील प्रजातंत्र है। इसमें यह कैसे संभव है कि कल का युवराज ही भविष्य में जनतांत्रिक आका बने। दीगर है कि उसके परिवार की गौरवशाली परंपरा ने आजादी के बाद देश को तीन प्रधानमंत्री ही दिए है।

इन स्थापनाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए ऐसी अनहोनी हुई कि एक चायवाला लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर बैठ गया। ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान का परिपक्व प्रजातंत्र अब राजसी खंडहरों को उनकी वास्तविक हैसियत बताने को कटिबद्ध है।

अर्थव्यवस्था को शराब का सहारा

सतीश एलिया

विश्वव्यापी महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रमुख उपाय माने गए लॉकडाउन के करीब डेढ़ माह में देश ने जो दृश्य देखे हैं, वे न भूतो हैं, भविष्यति के बारे में भविष्य ही बता सकेगा लेकिन वे दृश्य भयावह भी हैं और तसल्ली देने वाले भी। भयावह इस अर्थ में कि मौत का इस कदर भय और खतरा इस सदी में शायद पहले कभी महसूस नहीं किया गया। मौतों का बढ़ता आंकड़ा, संक्रमण की न थम रही रफ्तार और अपने घरों की ओर लौटने को सैकड़ों मील पैदल चलने को अभिशप्त बेरोजगार, गरीब मजदूरों के काफिले, चिकित्सा विज्ञान को झुठलाते और लोगों को बरगलाते मतांध समुदायिक नेता, कोरोना के अलावा भूख से मरते लोग और अपनों का अंतिम संस्कार से डरते हुए लोगों के भयाक्रांत चेहरे। तसल्ली यह कि लॉकडाउन की मंशा और मकसद का समर्थन करते लोग और एक-दूसरे की हौसला अफ्जाई में शंख ध्वनि से दीये रोशन करने से लेकर आसमान से फूल वर्षाती हमारी सेना, अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा और सुरक्षा और इलाज में जुटे लोग और उनका हौसला बढ़ाते घरों में कैद लोग।

कोरोना संकट के बीच पूरी दुनिया के देशों की तरह हमारे देश में भी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की चिंता पक्ष से लेकर विपक्ष और अर्थशास्त्री से लेकर अनर्थशास्त्री तक सब कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की राज्य सरकारों ने अपने अर्थशास्त्र को सम्हालने के लिए जो प्राथमिकता में एक सुर से जो बात की वह बहुत गहरे में चिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक भी है और बहुत गहरे में उस भारतीयता और गांधीवाद से भी सीधा जुड़ा मामला है, आर्थिक तो निरूसंदेह है ही। यह है शराब के कारोबार की अनुमति देने की लगभग सभी राज्यों की सरकारों ने पैरवी की क्योंकि यह राज्य सरकारों के सर्वाधिक आय वाले कारोबारों में सबसे ऊपरी पायदान में शामिल है। तो क्या मद्य निषेध के गांधीवादी सिद्धांत केवल दिखावे के लिए है, दो अक्टूबर गांधी जयंती को शराब दुकानें बंद रखने तक ही सीमित रखने योग्य है। गुजरात

और बिहार जैसे आधिकारिक शराबबंदी राज्यों में आम दिनों भी तस्करी के अजीब-अजीब तरीके सामने आते रहे हैं, वैसे ही दृश्य कोरोनाकाल में अन्य राज्यों में भी सामने आए। कहीं खाने की होम डिलीवरी करने वाले सप्लाय ब्यॉय के टिफिन में शराब के वाहक मिले तो कभी दूध सप्लाई की आड़ में शराब की तस्करी।

सोशल मीडिया में भले ही मजाक में सही शराब के विरह और उसके न मिलने की जो भाव अभिव्यक्तियां इस कोरोनाकाल में हुई हैं, सरकारों ने लॉकडाउन 2.0 खत्म होते ही इस कारोबार को प्राथमिकता दी है, उससे पता चलता है कि एक समाज, एक देश और अर्थव्यवस्था के तौर पर हम गांधी को नकारने का ऐलान कर रहे हैं। वह भी गांधीजी के जन्म क डेढ़ सौवां वर्ष मनाने के तमाम भाषणों, उफ्क्रमों में हमारे नेता उन्हें ही हमारे देश का सर्वाधिक उच्च आदर्श मानने के वादों को दोहराते रहे हों। किसी भी दल की सरकार हो , इस अभूतपूर्व कोरोना संकट काल में शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व की प्राथमिकता बताती है कि गांधी के दर्शन को हम केवल चर्चा में ही रख पाए हैं, अमल में नहीं ला सके। गांव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वाबलंबन, स्वदेशी, मद्य निषेध, स्वच्छता, सत्य आचरण, सादगी ही तो गांधी दर्शन हैं। हम केवल स्वच्छता में ही एक हद तक उनका अनुसरण करने का प्रयास करते दिख रहे हैं। मद्य निषेध के बजाए मद्य सर्वोपरि का सिद्धांत गढ़ने की मजबूरी बताती है कि आजादी हासिल करने के 74 साल बाद भी हम गांधी को नहीं अपना सके।

राज्यों के राजस्व का दारोमदार

हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारों का खासकर राज्य सरकारों की आय का मुख्य दारोमदार जिन तीन चीजों पर टिका है, उनमें शराब, पेट्रोलियम पदार्थों पर वसूले जाने वाला टैक्स, सेस और उपकर तथा संपत्तियों के क्रय-विक्रय के दस्तावेजों पर वसूले जाने वाला स्टांप शुल्क और उसके सहयोगी टैक्स ही प्रमुख हैं। कोरोना काल में पेट्रोल-डीजल की बिक्री से मिलने वाला टैक्स शून्यप्राय है, पंजीयन शुल्क इत्यादि मिलने का तो प्रश्न ही नहीं, बाकी के कारोबार से प्राप्त टैक्स भी सीमित मात्रा में अत्यावश्यक सामग्रियों के विक्रय की अनुमति में भी सरकार नहीं वसूल सकी क्योंकि इस संकट काल में बहुधा व्यापारियों ने बिल देने और टैक्स सरकार तक पहुंच सके इसकी जहमत न उठाना ही लाभ का धंधा मानकर कारोबार किया। सरकार अब अत्यावश्यक कारोबार मानकर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे चुकी है, उसके साथ ही सेहत के लिए घातक गुटखा, बीडी सिगरेट भी उपलब्ध हो सकेंगे। नशे के कारोबार के सहारे खड़ी हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत गहरे चिंतन की जरूरत है। सब जानते हैं कि नशा समाज के लिए सर्वाधिक घातक है।

सोशल मीडिया पर वायरल

चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों और पुलिस कर्मियों को कोराना वारियर्स मानकर उनके लगातार जारी सम्मान के बीच अब जबकि शराब के कारोबार को अर्थव्यवस्था का सहारा मान लिया गया है तो सोशल मीडिया पर यह मजाक खूब चल रहा है कि जब कोई शराब खरीदकर लौटे तो उसपर भी पुष्प वर्षा हो कि वह भी अर्थव्यवस्था चलाने और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने में मदद कर रहा है। यह मजाक हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर तीखा कटाक्ष माना जाना चाहिए। यह उम्मीद भी कि कोरोना संकटकाल के बाद हम हमारी आंतरिक और राज्यीय अर्थव्यवस्था में शराब के कारोबार की महत्ता को कम कर सकें, यही महात्मा गांधी के 150 वें जन्म वर्ष को मनाने की सार्थकता हो सकती है। फिलहाल तो शराबबंदी के अभ्यास को जारी रखने के पक्ष में न न वे हैं जो गांधी को अपनी पार्टी की विरासत और विचारधारा बताने का दावा आजादी से अबतक कर रहे हैं और न वे जो गांधी से मतांतर रखने वाली विचारधारा के वाहक होने के बावजूद गांधीवाद को अपना दर्शन मानने और उसे समर्थन और प्रसार देने के लिए संकल्पबद्ध होने का संकल्प बार-बार व्यक्त करते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

स्वयंभू दलाल कर्मचारी नेता से कलेक्टर, एस पी सहित जिले के आला अधिकारी रहें सावधान

माही की गूंज, धार।

भारतीय पत्रकार संघ एआईजे मध्यप्रदेश के प्रदेश सचिव ने कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारियों, तहसील, विकासखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे जिला मुख्यालय पर मंडराने वाले एक स्वयंभू कर्मचारी नेता से सावधान रहें, क्योंकि यह नेता आए दिन अफसरों के चेम्बरों में जाकर दलाली का काम करता है और कर्मचारियों को यह संदेश देता है कि मेरे संबंध अधिकारियों से घनिष्ठ हैं। कर्मचारियों से अधिकारी के नाम पर रुपए लेकर उनके काम करवाने का दावा करता है, फिर चाहे काम हो या न हो। ऐसे में अधिकारी बदनाम होता है। आपको बता दें यह छुटभैया नेता लॉकडाउन व कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों को साथ लेकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारियों के पास पहुंच जाता है और राहत कोष में राशि जमा करवाने के आव्हान का पत्र मात्र दिखाकर वाहवाही लूटने का भी कार्य कर रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि राहत कोष में राशि जमा कराने के नाम पर पैसे की मांग भी जा रही हैं। अनेकों कर्मचारियों को ये स्वयं भू नेता बड़े अधिकारियों का नाम लेकर फोन लगा रहा है कि राहत कोष के लिए राशि इकट्ठा कर के मुझे दो मैं आगे दूँगा। ऐसे में राशि में घोटाले से इंकार नहीं किया जा सकता है।

खुद ही कुछ संघों के मोर्चे का अध्यक्ष खुद को बताकर वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश में रहता है और खुद के स्कूल में भी यदा-कदा ही टाइम बे टाइम जाता है। अनेकों कर्मचारी इस दलाल नेता के विरुद्ध इस बात का शपथ पत्र देने को तैयार है कि इस छुटभैये नेता ने काम करवाने के नाम पर उनसे मोटी रकम ऐंठ ली, और काम कराने के नाम पर शाम की पार्टी भी खा गया। लेकिन उनका काम नहीं हुआ। हर किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत रखने वाले इस छुटभैया नेता के साथ जो भी रहा उसका नुकसान ही हुआ है। आरोप है कि सुरा सुंदरी का शौकीन यह दलाल नेता आए दिन कलेक्टर कार्यालय, ट्रेजरी, एसडीएम आफिस, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला अस्पताल, नगरपालिका कार्यालय, कृषि विभाग, जनपद पंचायत, सहायक आयुक्त आदिम जाति कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा केन्द्र आदि कार्यालयों में सभी तरह के कर्मचारियों को अपने साथ काम के नाम पर घुमाता नजर आता है। ऐसे में कार्यालयों के बाबू इस छुटभैये के जाते ही चटखारे ले कर बाते करते दिखते हैं। आपको बता दे इस छुटभैये कर्मचारी नेता ने पिछले दिनों पत्रकारो के विरुद्ध कुछ लोगों के साथ मिलकर ज्ञापनबाजी भी की थी और प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया था। ऐसे में कलेक्टर, एसपी के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारियों को भी इस दलाल से सावधान रहने की जरूरत है।

नए आदेश के बाद तुलावटी एवं हम्मालों को किया बंद

हम्मालों ने मंडी गेट पर कर दिया हंगामा, की नारेबाजी, कर्मचारियों पर लगाया ढील पोल का आरोप

माही की गूंज, सनावद।

मंडी के गेट पर हेम्मालो ने विरोध प्रदर्शन कर किया हंगामा।

मंडी के बाहर प्राईवेट काटे पर वाहनो की लाईन लगी कुछ इस तरह लगी रही।

नगर की कृषि उपज मंडी में नए आदेश के बाद तुलावटी एवं हिम्मलो को काम से बंद कर दिया गया। जिसके बाद करीब 30 से अधिक तुलावटी एवं हिम्मलो ने मंडी गेट पर हंगामा कर दिया। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए मंडी के स्थानिक कर्मचारियों की ढील पोल का आरोप लगाया। कृषि उपज मंडी सचिव डीएस परिहार के अनुसार कोरोना वायरस के कारण विगत 15` अप्रैल से मंडी बंद थी। लेकिन तुलावटी एवं हम्मलो ने बताया कि मंडी में कार्य जारी था। जो बाहर के निजी तोल काटे पर तुलाई के बाद मंडी व्यापारियों के मंडी एवं निजी गोदामो पर रखा जाता था। लेकिन नए आदेश के बाद अब मंडी पूर्णता बंद कर दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की अवधि में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन के मंडी बोर्ड द्वारा एक पत्र 13 अप्रैल को भेजा गया था। जिसमें कृषि उपज मंडी में किसानों की कृषि उपज का क्रय विक्रय की अनुमति दी गई थी। कुछ मंडी समितियों से सूचना आई कि सौदा पत्रक में कृषि उपज खरीदी में कृषि उपज का तोल एवं हम्मली का कार्य मंडी के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल तथा तुलैया द्वारा न किए जाने पर किसानों से हिम्मलि ओर तुलाई की राशि काटी जा रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विक्रय संव्यवहार जिसमें तुलाई एवं हम्माली का कार्य नहीं किया गया। ऐसे कृषि विपणन संव्यवहार में किसानों से हम्माली एवं तुलाई की राशि काटा जाना विधि प्रक्रिया के विपरीत है। किसान से इस प्रकार की राशि नहीं काटा जाना सुनिश्चित करे। लेकिन विभाग को आए पत्र के बाद मंडी में काम करने वाले हम्माल एवं तुलावटी अब इस काम से वंचित रहेंगे। तुलावटी गोपाल भाकड़ ने बताया किसान व व्यापारियों की प्रत्येक खरीदी पर हम्माली व तुलाई कटती है। जिसके बदले किसान व व्यापारी प्रत्येक क्विंटल पर 5-5 रुपए देते हैं। जिसमें से 7 रुपए हम्माल व 3 रुपए तुलाई वाले को मिलते हैं। यहां पर पंजीकृत करीब 400 हम्माल काम करते हैं। जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है। लॉकडाउन के कारण करीब एक माह मंडी बंद रही थी। अब अफसर हम्माल व तुलाई के रुपए काटने पर रोक लगा रहे हैं। जबकि हम्मालों व व्यापारियों ने लिखित में मंडी सचिव को रुपए काटने पर सहमति का आवेदन भी दिया है। इसके बाद भी हम्मालों व तुलाई वालों को काम करने से रोका जा रहा है। जो गलत है। अगर हम्माली व तुलाई नहीं मिलेगी तो काम करने से कोई मतलब नहीं है। इस लिए काम बंद कर दिया है।

हम्माल हरनामसिंह सोलंकी ने बताया कि सरकार के नियम अनुसार किसान व व्यापारी बाहर से सौदा पत्रक कर माल की मंडी परिसर में ही तुलाया जाता तो किसानों को तुलाई के रुपए नहीं देना पड़ते।

मंडी में 15 से चल रहा था व्यापारियों का सौदा

लॉकडाउन के दौरान किसानों को सुविधा देने के लिए सरकार ने बाहर से खरीदी कर मंडी में अनाज रखने के लिए 15 अप्रैल से व्यापारियों व किसानों को आने की अनुमति दी थी। जिससे किसान सौदा कर व्यापारियों का माल मंडी में ही उतारते थे। जिससे मंडी में भीड़ लगी रहती थी। वहीं पर हम्माल व तुलावटियों को मजदूरी देते थे।

नए आदेश आते ही पुनः काम दिया जाएगा

इस संबंध में प्रभारी मंडी सचिव सनावद डीएस शेखावत ने बताया कि किसानों को उपज बेचने के बाद भुगतान किया जाता है। उसके बाद ही विक्रय पत्रक मिलता है। वहीं नए आदेश के बाद हाड़ौलिक तोल काटा होने से तुलाई एवं हिम्माली के कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस लिए हिम्माल एवं तुलावटियों को काम से बंद किया है। नए आदेश आते ही पुनः इन्हें कार्य दिया जाएगा।

आईजी शर्मा ने किया निरीक्षण

माही की गूंज, सनावद। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं अनेक लोग ऐसे है जो इस बीमारी से पीड़ित होकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के कारण इसका असर सहन कर गए। और उनकी यह बीमारी ठीक हुई। आप लोग भी करुणा से डरे नहीं। पुलिस जवान पुलिस पाइंट के साथ साथ संक्रमित क्षेत्रो में भी बखूबी काम कर रहे है। पिछले 45 दिनों से जैसे आप लोग घर वालों से दूर होकर कार्य कर रहे हैं। वैसे हम भी इस कार्य में लगे हैं। आप किसी भी समस्या को लेकर मुझ से सीधे संवाद कर सकते हैं। यह बात आईजी विवेक शर्मा ने नगर के पुलिस थाने के निरीक्षण के दौरान कहे। शर्मा ने सनावद एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को जानते हुए यहां पदस्थ स्टाफ से खुलकर चर्चा की। साथ ही उन्हें बताया कि कोरोना की से डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी इसका डटकर मुकाबला करेंगे। तो जल्दी यह बीमारी प्रदेश से बाहर होगी। शर्मा ने थाने में पदस्थ प्रत्येक स्टाफ से रूबरू चर्चा की। साथ ही बाहर से आए पुलिस स्टाफ जो होटलों में रह रहे हैं। उनसे भी स्थिति को जाना। शर्मा ने टीआई राजेन्द्र सोनी को निर्देश दिए कि सप्ताह में 1 दिन अलग-अलग क्रम बनाकर पुलिसकर्मियों को अवकाश दिया जाए।

करोना महामारी के बारे में ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक

माही की गूंज, सनावद।

कोरोना की इस महामारी में जहां प्रशासनिक अमला अलग-अलग क्षेत्रों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने का कार्य कर रहा है। वहीं क्षेत्र में अनेक समाजसेवी संस्था राशन सहित खाद्य सामग्री देकर सैनिटाइजर मावस का वितरण कर रही है। कोविड-19 की इस परीक्षा की घड़ी में सामाजिक कार्य करने वाली संस्था अनंत जीवन सेवा एवं शोध समिति द्वारा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर करोना महामारी के बारे में आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही इस बीमारी से बचने के लिए घरो मे रहने की सिख दे रहे है। संस्था की अध्यक्ष ज्योति कुमरावत ने बताया कि हम सब कोरोना वायरस से फैल रही महामारी के साथ संघर्ष कर रहे है। जहां एक और कोरोना वायरस इतना घातक है कि इसका कोई इलाज नहीं है। वही दूसरी और इससे बचाव का तरीका अत्यंत सरल है। कुछ दिन हम सभी सामाजिक दूरी बनाकर करोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संस्था द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी की रोकथाम के लिए हाइजीनिक मावस बनाए गए। जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर निशुल्क वितरित किया गया। कुछ गरीब जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस दौरान लोगो से सामाजिक दूरी बनाने के साथ साथ बचाव के साथ रहने की बात समझाई जा रही है। वही ग्रामीण भी संस्था सदस्यो को भरोसा दिलाते हुए नियमो का पालन करने का भरोसा दिला रहे है।

ये कैसी सामाजिक दूरी है बैंक के बाहर..?

माही की गूंज, बामनाला।

जब हम कोरोना पर लगभग विजय पा रहे है तो ऐसे में इस तरह की लापरवाही हमें फिर पीछे धकेल सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा ? जिले के सबसे बड़े कस्बे बमनाला का हाल-ए-दर्द, आप फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते है। बैंको के बाहर पैसे निकालने को लेकर लगी ग्रामीणों की अथाह भीड़ ने लॉकडाउन के सारे नियमों को ताक में रख दिया। सामाजिक दूरी के नियम की यहां खुले आम धज्जियां उड़ती देखी गई। कोरोना के कहर के बीच संकट में डाल देने वाली यह तस्वीर मन को झकझोर रही है। बैंकों के बाहर लगी भीड़ यह दर्शा रही है कि हम कोरोना को कितनी गम्भीरता से ले रहे है। बैंक के बाहर हुई भीड़ की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बैंक मैनेजर को खातेदारों की समस्या को हल करने के निर्देश दिए। लेकिन बैंक मैनेजर ने इसमें असमर्थता जताते हुए कहा कि हमें पुलिस सिक्युरिटी चाहिए।

31 मई को होने वाली सिविल सेवा (आरंभिक) परीक्षा, 2020 स्थगित

संघ लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई। प्रतिबंधों के विस्तार पर विचार करते हुए आयोग ने फैसला किया कि वर्तमान हालात में परीक्षाएं और साक्षात्कार फिर से शुरू करना संभव नहीं है।

इसलिए 31 मई, 2020 को प्रस्तावित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 को स्थगित कर दिया गया है। चूंकि यह परीक्षा भारतीय वन सेवा परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में भी कार्य करती है, इसलिए भारतीय वन सेवा परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। 20 मई, 2020 को फिर से परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों के बारे में उचित समय पर यूपीएससी की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

आयोग पहले ही आगे उल्लिखित को टाल चुका है रू (क) सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के लिए शेष अभ्यर्थियों के लिए व्यक्तित्व परीक्षणय (ख) भारतीय आर्थिक सेवाध्भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 के लिए अधिसूचनाय (ग) संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 के लिए अधिसूचनाय (घ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2020 के लिए अधिसूचना और (ङ) एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा, 2020 स्थगित परीक्षाओं के लिए जैसे ही और जब भी फैसला किया जाता है, सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों को कम से कम 30 दिन पहले सूचना दे दी जाए।

अच्छी क्वालिटी का कपास खरीदने जा रही है सीसीआई

माही की गूंज, भीकनगांव। समस्त भीकनगांव मंडी क्षेत्र के किसानों को सूचित किया जाता हैं कि सीयसीय आई द्वारा एफएक्यु (गुणवत्ता पूर्ण क्वालीटी) का कपास भीकनगांव क्रय केन्द्र पर बुधवार से प्रारंभ किया जा चुका हैं। कपास बैचने के इच्छुक किसान रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन प्रातः 10.30 से 4 बजे तक किए जा रहे है। रजिस्ट्रेशन पश्चात दिए गए दिनांक को कपास विक्रय हेतु लाएं। एक दिन में केवल 20 से 25 वाहनों को ही क्रय किया जाएगा। हल्का तथा नमी युक्त कपास सीसीआई द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। एक हेक्टेयर में 15 क्विंटल के हिसाब से क्रय किया जाएगा।

कोरोना पीड़ितों की चिकित्सा से अपना कैरियर आरंभ करेंगे डॉ. गुरुयशसिंह कपूर

माही की गूंज, सनावद।

नगर की विमला कॉन्वेंट स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र डॉ. गुरुयशसिंह कपूर चिकित्सक की उपाधि प्राप्त कर मंगलवार को कोरोना मरीजों की चिकित्सा हेतु इंदौर रवाना हुए। स्थानीय गुरुद्वारा साहिब में गुरूसिंघ सभा के अध्यक्ष पृथ्वीपालसिंह कपूर एवं समाजजनों ने डॉ. कपूर का अभिनन्दन किया और सरोपा भेंट किया।ज्ञानी त्रिलोचनसिंह खालसा ने डॉ. कपूर को आशीर्वाद प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि डॉ. कपूर,समाजसेवी तेजेंदरपालसिंह कपूर एवं पार्षद अमरदीप कौर कपूर के पुत्र हैं । डॉ. कपूर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विमला कॉन्वेंट स्कूल में पूर्ण की। तत्पश्चात भोपाल के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त की। हाल ही में मप्र शासन ने डॉ. कपूर की नियुक्ति सीएमएचओ हॉस्पिटल इंदौर में की है।जहां डॉ. कपूर कोरोना पीड़ितों की चिकित्सा से अपना कैरियर प्रारंभ करेंगे।वरिष्ठ समाजसेवी मोहनलाल दुआ ने कहा कि डॉ. कपूर ने सनावद नगर का नाम रौशन किया है और चिकित्सा के उच्च आदर्शों के अनुरूप कोरोना जैसी खतरनाक संक्रामक महामारी से पीड़ित मरीजों की चिकित्सा का पुनीत कार्य आरंभ कर रहे हैं। इस दौरान समाजसेवी महिंदर नरूला,राजा भाटिया,राकेश नरूला,चिंटू खनूजा,कंवलजीत खनूजा,यशवंत देवाणी आदि उपस्थित थे।विधायक सचिन बिरला और थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने भी डॉ. कपूर को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

अधिकारियों ने किया ग्रामीण क्षेत्र के क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण

माही की गूंज, सनावद।

कोरोना वायरस के बाद नगर एवं जिले में प्रशासन सतर्क होकर सतत नजर बनाए हुए हैं। वही सनावद एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले मजदूरों के लिए गांव में ही क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। यहां पर मजदूर अगले 14 दिनों तक रुकेंगे। ग्राम चित्रमोड बोधगांव हीरापुर ढकलगांव छापरा सहित अन्य ग्रामो में अस्थाई क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाये गए है। इन्ही सेंटर एवं वहां की व्यवस्था को देखने के उद्देश्य से रविवार को नायब तहसीलदार सुखदेव डाबर टीआई राजेन्द्र सोनी अलग-अलग ग्रामो में बने अस्थाई क्वॉरेंटाइन सेंटर पहुंचे। हीरापुर सहित अनेक स्थानों पर यहां रहने वाले मजदूर बाहर धाड़की के लिए गए थे। जहां पर कोरोना वायरस वाले क्षेत्रो से आये मजदूरों को घरों में नहीं रहते हुए 14 दिनों तक गांव में बने अस्थाई क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने के निर्देश दिए गए थे। जहां पर उनके रहने की व्यवस्था भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए वहां निरीक्षण किया। वही सेंटर में मौजूद अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा-निर्देश भी दिए थे। डाबर ने बताया कि नगर एवं कस्बे के नागरिक बाहर से आने वाले लोगो से सतर्क रहकर इनके आने की सूचना सबंधित अधिकारी को तत्काल देवे। टीआई सोनी ने बताया कि आगे भी आने वाले मजदूरों को क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। जिससे किसी भी संभावना से बचा जा सके। प्रशासन नगर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। एवं स्थिति से निपटने में सक्षम है।

बुरहानपुर कोरोना का नया हॉट स्पाट, मरीजो का आंकड़ा 35 पहुंचा, 3 की मौत

माही की गूंज, बुरहानपुर।

मध्यप्रदेश का बुरहानपुर चीनी वायरस कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है। सोमवार को 16 और नए मरीज आने से जिले में हडकंप है। प्रशासन-पुलिस सकते में है। कलेक्टर प्रवीणसिंह अढ़ाईच ने बताया कि आए 116 सैंपलों में से 16 सैंपल कोरोना पॉजिटिव और 100 सैपल नेगिटिव है। उन्होने बताया कि बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। इनमें 3 मरीजों की मौत हुई है। हांलाकि यह सभी मौतें सैंपल लेने के बाद और रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले हुई है। इससे चिंताएं बढ़ी है। मृतकों में एक महिला और 2 पुरूष है। यह सभी उम्र दराज है और अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित थे। मृतक महिला मोमीनपुरा के दीक्षित गली की है। मृतक पुरूष सिंधीपुरा के पाटीदार कॉलोनी और उपनगर लालबाग के सागर टॉवर एरिया के है। अधिकतर संक्रमित मरीज दाऊदपुरा के पूर्व पार्षद के संपर्क वाले है। एक सप्ताह पूर्व इस पूर्व पार्षद के कोरोना संक्रमित पाएं जाने पर उसके संपर्क वाले लोगों के सैंपलों की जांच रिपोर्ट से बुरहानपुर में कोरोना मरीजों की बाढ़ आई है। उस पूर्व पार्षद के पहले बुरहानपुर में कोरोना की सिर्फ एक महिला मरीज थी। वह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मल्कापुर से आई थी।

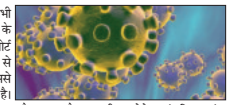

संभागायुक्त ने किया दौरा

सोमवार को इंदौर संभाग के आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बुरहानपुर का दौरा कर हालात का जायजा लेकर स्थिति की समीक्षा कर विभिन्न व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित मरीज 35 हो गए है। इनमें से 3 की मौत हुई है। बुरहानपुर ग्रीन झोन से निकलकर रेड झोन में आ गया है।

स्वास्थ्य विभाग में चल रही धांधली

पूर्व सिविल सर्जन के रिक्त पड़े आवास पर स्टीवर्ड ने किया कब्जा

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों आवास आंवटन में हो रही धांधली को लेकर चर्चा में बना हुआ है। शासकीय आवास नियम संबंधी नियमों को बलाय तांक पर रखकर मनमाने तौर पर आवासगृहों का आंवटन किया जा रहा है अथवा रसूखदार कर्मचारी मनमाने तौर पर अधिकारियो के लिये बनाये गये आवासों में अधिकारी के सेवा निवृत्त होते ही बलात रूप से उस आवास गृह में कब्जा करने मे कोई कोताही नहीं बरत रहे है। ओर जिला स्तर पर बैठे सक्षम अधिकारी इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे है।

हांल ही में एक ऐसा मामला जिला चिकित्सालय परिसर में सामने आया है जिसमें पूर्व सिविल सर्जन डॉ आरएस प्रभाकर जो शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त हुए है। उनके जिला चिकित्सालय परिसर स्थित आवास पर जिला अस्पताल के प्रभारी स्टीवर्ड जो निम्न श्रेणी लिपिक पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे है। तथा जिन्हें जिला मुख्यालय पर ही स्वयं का आलिशान निजी बंगला होने के बाद भी उनके द्वारा सिविल सर्जन के उक्त सरकारी आवास पर कब्जा करके उसमें निवास करना प्रारंभ कर दिया है तथा भवन पर अपनी नेम प्लेट तक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग में बहुचर्चित निम्न श्रेणी लिपिक के पद के समकक्ष काम करने वाले प्रेम कुमार डेनियल जो हमेशा ही विवादो के घेरे में रहे है। कभी सीएमएचओ कार्यालय अपना दबदबा बनाकर स्वयं भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे है। तथा झोलाछाप डॉक्टरों से संपर्क स्थापित कर तथा उन्हें येन केन प्रकारेण बचाने में अपनी भूमिका निभाने तथा अधिकारियों को चंदीचारा दिलाने में अग्रणी रहे है। पात्रता नहीं होते हुए भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लेखापाल का चार्ज लेकर भ्रष्टाचार करने में अग्रणी रहे है। वही इनके कई कारनामें विभाग में चर्चा का विषय बने हुये है। ऐसे प्रेम कुमार डेनियल ने सिविल सर्जन प्रभाकर के रिटायर्ड होते ही उनसे उक्त शासकीय आवास की चाबी इस आशय से प्राप्त की थी वह विभाग के अधिकारी को सौप देंगे। किन्तु ऐसा नहीं करते हुये स्वयं ने ही उक्त आवास पर जबरन कब्जा कर लिया और इसमें निवास करना भी प्रारंभ कर दिया है।

पूर्व सिविल सर्जन के शासकीय आवास पर स्टीवर्ड ने किया कब्जा ।

शासकीय आवास नियम के बिन्दु 5 के उपबिन्दु 2 के अनुरूप इनका निजी आलिशान बंगला होने के बाद भी किस आधार पर इनके द्वारा प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिये बनाये गये शासकीय आवास पर कब्जा किया है। यह जांच का विषय है। वैसे भी किसी शासकीय आवास पर जबरन कब्जा करना शासकीय सेवक आचरण संहिता के तहत दण्डनीय अपराध होने के बावजूद भी ना तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एव ना ही जिला अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर प्रभावी कार्यवाही की। बरसो से अंगद के पांव की तरह झाबुआ में जमे हुये इस भ्रष्ट कर्मचारी के द्वारा राजनितिक रसुक का हवाला देकर लाभ उठाना आम बात हो गई है। शिवराज सरकार आने के पूर्व जो कर्मचारी खुले आम कांग्रेस सरकार के गुणगान करने में पिछे नही रहता था वही अब पाला बदलकर कर्मचारियो पर रोब झाडने मे तथा उन्हे भयभीत करने मे कोई कसर बाकी नही रख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने आवास आवंटनो को लेकर अनियमितता का उदाहरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेघनगर में भी देखने को मिला है। जहां खंड विस्तार प्रशिक्षक जिन्हें विभाग के नार्म के अनुसार एच टाईप क्वार्टर की पूरे मप्र में पात्रता है। वहा इसे भी दरकिनार करके हाल ही मे पदस्थ हुई एक स्वास्थ्य अभ्यागिता को अलाट करवाने में भी इनका हाथ होने की चर्चा बनी हुई है । यदि जिला प्रशासन आवास आंवटन नियमो के तहत तथा विभागीय नार्म के अनुरूप आवास आंवटनो की जांच करवाये तो निश्चित ही कई तथ्य सामने आ सकते है।

इनका कहना है -

प्रेम कुमार डेनियल का आवास आंवटन के लिये दिया गया आवेदन आवास आंवटन समिति ने निरस्त कर दिया है। इन्हे क्वार्टर विधिवत अलाट नहीं हुआ है। इन्होंने मकान पर कब्जा किया है। इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। **डॉ. बी एस बघेल सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय झाबुआ।**

कोरोना के हाट स्पॉट बने कुशलगढ में निकला फ्लैगमार्च, नगरवासियों ने किया स्वागत

माही की गूंज, कुशलगढ़।

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हॉटस्पॉट बने कुशलगढ़ कस्बे में रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधव सिंह के नेतृत्व में उप अधीक्षक संदीप सिंह शक्तावत, बांसवाड़ा उप अधीक्षक नगराज शामरिया,थानाधिकारी कैलाश खटीक,प्रतापगढ़ थाना थानाधिकारी गहरीलाल, उदयपुर थानाधिकारी तेजकरण आदि के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में क्यूआरटी, महाराणा प्रताप बटालियन, एमबीसी, आरएसी होम गार्ड, पुलिस जवान शामिल थे। फ्लैग मार्च टिमेड़ा बस स्टैंड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गो से होता हुआ पुनः टिमेड़ा बस स्टैंड पहुंचा। जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधव सिंह ने जवानों को निर्देश देते हुए कहा कि हमें जनहितों का ध्यान रखना है और उनकी समस्याओं को देखकर मानवीय दृष्टिकोण भी रखना है। उन्होंने कहा कि जनता ने 40 दिनों तक निर्देशों की पालना किया है, वह भी बधाई की पात्र हैं। साथ ही आशा कि है कि हम शीघ्र इस महामारी पर विजय पताका फहराएंगे। इस बीच नगरवासियों द्वारा जगह-जगह वाद्ययंत्रों, तालियों, गुलाल, पुष्प से जवानों का भव्य स्वागत किया गया।

कोरोना महामारी को लेकर बनी आपदा प्रबंध समिति पूर्णतः विफल

प्रशासनिक तानाशाही के शिकार हो गए मजदूर

माही की गूंज, झाबुआ।

कोरोना महामारी को लेकर कहने को तो जिला प्रशासन ने एक जिला स्तरीय आपदा प्रबंध समिति का गठन किया है जिसकी कई बैठकें जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में कर ली है परंतु देखने में आ रहा है कि आपदा और प्रबंध समिति कोरोना महामारी को लेकर लड़ने में पूर्णता विफ्ल साबित हो रही है जिसका ज्वलंत उदाहरण पिछले दिनों गुजरात की सीमा से लगे पिटोल बॉर्डर पर देखने को मिला गुजरात से आए हुए हजारों मजदूरों को बच्चों को स्तिरयों को भूखे प्यासे तड़पना पड़ा और यह सब प्रशासनिक तानाशाही के शिकार बने जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया की बदनामी हर जुबां पर प्रदर्शित हो रही थी और यह सब कार्य जिले की प्रशासनिक इकाई के द्वारा दूरदर्शिता एवं संवेदन हीनता के कारण यह स्थिति निर्मित होती हुई नजर आई प्रत्यक्षदर्शियों एवं प्रेस जगत के प्रतिनिधि द्वारा जो देखा गया और जो बयां किया गया वह दर्दनाक और शर्मनाक था तानाशाह बने झाबुआ के एसडीएम अभय खराड़ी अपनी सारी मानवता को भूल गए थे और टेंट में बैठे हुए मजदूरों स्त्रियों एवं बच्चों को यह खदेडने का काम कर रहे थे भोजन बना हुआ था परंतु भोजन भी तानाशाह के चलते मजदूर भोजन नहीं कर पाए नन्हे नन्हे बच्चे दूध और पानी के लिए बिलखते हुए नजर आए हर कोई मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को कोसता हुआ नजर आया यह स्थिति झाबुआ जिले में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही एवं एवं संवेदनहीनता के चलते परिलक्षित हो रही थी जिसके चलते हजारों की संख्या में गुजरात से आए मजदूरों ने वहां गदर मचा दिया जिसके चलते बसों एवं जीपों के कांच फोड़ दिए गए जबकि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने करोड़ों का बजट कई गुना महामारी से निपटने के लिए झाबुआ जिले के प्रशासनिक इकाई को दिया है परंतु इस बजट का यहां के प्रशासनिक इकाई अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे की तर्ज पर प्रशासनिक अधिकारी एवं उनके लगु भग्गू पत्रकार एवं व्यापारियों ओर कर्मचारीयो को गुपचुप गुपचुप ढंग से आए दो करोड़ के बजट के ई टेंडर निकाल कर बंदरबांट करने के भी समाचार गुलाबी बिल्डिंग के गलियारों से छनकर हमारे पास आ रहे हैं इसमें प्रशासनिक मुखिया से लगाकर कई अधिकारी गुलाबी बिल्डिंग के शामिल है। कहने वाले कहते हैं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार काबीज हो चुकी है परंतु उससे जुड़े जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी हो रही गड़बड़झाला को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। यह यक्ष प्रश्न जनता के बीच बना हुआ है कहने वाले कहते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई जिला स्तरीय आपदा और प्रबंधन समिति के चयन में विषय विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया है और फील्ड से जुड़े सदस्यों को दरकिनार कर अपरिपक्व लोगों को शामिल कर औपचारिकता को पूर्ण किया जा रहा है इसमें कई ऐसे संगठन के सदस्य जो अपने आप को समाजसेवी कहते हैं, पर समाज सेवा के नाम पर करोना महामारी को लेकर आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया सिर्फ आपदा प्रबंध समिति में उपस्थित होकर अपना रुआब गालिब करते हैं जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान दें। जिले में कई बस ऑपरेटरों के पास बसे उपलब्ध है फिर भी जिला प्रशासन मजदूरों को पहुंचाने के लिए उन ऑपरेटरों से बस क्यों नहीं मंगा रहा पिटोल बॉर्डर पर यह भी गुलाबी बिल्डिंग में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जिला प्रशासन से कोरोना महामारी से निपटने के लिए आए दो करोड़ का बजट का कहां और कैसे खर्च किया गया है क्या-क्या सामग्री क्रय की गई है का जवाब प्रशासन से जनता मांगते हुए नजर आ रही है कब हो गए टेंडर कब हुए आर्डर और कब आए सामग्री इसका जवाब जिला प्रशासन तुरंत दे। कहने को तो जिला प्रशासन जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति बनाकर उसके कई बैठकें करके उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है पर धरातल पर और वास्तविकता में नजारा कुछ और है जिले की सीमाओं पर अन्य क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों की न तो प्रशासन द्वारा समुचित मेडिकल की व्यवस्था की गई है जांच की और न उनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई है बाहर से आने वाले कोरोना संक्रमित लोगों को रोकने का प्रयास भी प्रशासन द्वारा समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के दोहरी नीति के चलते हमने ऊपर पहले लिख दिया है अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे की तर्ज पर जिले में कई बस ऑपरेटर हैं जिनकी बसें अभी करोना के चलते नहीं चल रही है उन बसों को जिला प्रशासन मजदूरों की आवाजाही के लिये नहीं लगा रहा है सिर्फएक बस ऑपरेटर की बसों को ही ईगेज कर लगाना और उसमें रेड क्रॉस के माध्यम से डीजल भराने की चर्चा गुलाबी बिल्डिंग के सूत्रों के अनुसार जो प्राप्त हो रही है वह चौंकाने वाली है रेडक्रास का पैसा डीजल मे खर्च किया जा रहा है जिसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार होने की भी खबरें आ रही है हमने पूर्व में हमारे लोकप्रिय समाचार पत्रों के माध्यम से यह तथ्य उजागर कर दिया था कि जिले में पदस्थ आला अधिकारी कोरोना के आड़ में भी चांदी काटने में लगे हैं बताया जाता है कि अन्य बस ऑपरेटर की बसों को मजदूरों को भेजने के लिए क्यों नहीं लगाया जा रहा है यह यक्ष प्रश्न जनता के बीच में बना हुआ है जिसके कारण पिटोल बॉर्डर पर भगदड़ मच रही है ओर मारा मारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा कोरोनावायरस कर्मचारी और अधिकारियों को कीट इत्यादि सुरक्षा के सामग्री संपूर्ण जिले में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो फिर बजट कहां खर्च किया जा रहा है यह जन चर्चा का विषय बना हुआ है। विगत दिवस पिटोल बॉर्डर पर मजदूरों द्वारा किए गए हंगामे का कारण प्रशासनिक तानाशाही और लापरवाही है, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब प्रशासन के तानाशाही से उबकर मजदूर गदर करने पर आमादा हो गए तब वहां उपस्थित झाबुआ जिले के कलेक्टर व अन्य अधिकारी वहां से नौ दो ग्यारह हो कर गुजरात के खंगेला बॉर्डर पर पहुंचकर थम गए जबकि उन्हें पिटोल बॉर्डर पर रहकर गदर को शांत करने की ड्यूटी निभाना चाहिए थी परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिले में आपदा और प्रबंधन समिति पूर्णतया अपने कार्यों में विफ्ल हो गई है सिर्फबैठकों का आयोजन कर यह खानापूर्ति करने में लगी है और आए हुए बजट को बंदरबांट कर हजम करने में लगी है ऐसी जन चर्चा गुलाबी बिल्डिंग से लगाकर राजनीतिक गलियारों एवं पत्रकारिता के गलियारों में व्याप्त है। जिला प्रशासन जहां संपूर्ण जिले में पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की बात कर रहा है वही देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण जनता एवं पंचायतों से जुड़े पंच और सरपंच खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचने की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं यहां तक कि ग्रामीण पंचायतों के सरपंच जिला प्रशासन को ई डिमांड कर खाद्य आपूर्ति की मांग कर रहे हैं परंतु कलेक्टर और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है यह संपूर्ण जिले के हालात हैं फिर भी इन महत्वपूर्ण विषयों में जिला आपदा और प्रबंधन समिति में चर्चा ना होना आश्चर्य का विषय बना हुआ है तत संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अंत्योदय समिति के पूर्व उपाध्यक्ष दौलत भावसार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि उक्त समाचार में छपे तथ्यों की जांच उच्च स्तरीय समिति बनाकर करवाई जाए ताकि भ्रष्टाचार उजागर हो सके तथा अधिकारियों की दुर्नीति भाजपा सरकार को बदनाम करने की जिले में चलाए हुए हैं उस का भंडाफोड़ हो सके।

मजदूरों की आह ने बदला अंत्योदय का सपना

माही की गूंज। धवल अरोरा, स्वतंत्र पत्रकार

अंत्योदय अंत्योत्पीड़न में परिवर्तित हो रहा है। इसको लेकर सरकारें और हमारा तंत्र अपनी भूमिका निभाने में शून्य नजर आ रहे है। देश के कोने-कोने से आ रही श्रमिकों की हृदय विदारक तस्वीरें कहीं न कहीं हमारी सरकारों के दांवों व मानवता तार-तार कर रही है। सरकारों के प्रबंध शून्य दिखाई दे रहे हैं और श्रमिक सरकारों को श्रापित करता रेल की पटरियों, सड़कों पर मीलों पैदल चल रहा है। तो कोई दूध मुंहे बच्चें को लेकर तपती धूप में जल रहा है। इन सब के मन में केवल एक ही चाह है कि अपने घर को पहुंचे। श्रमिकों का पलायन अब तक बहुत सुना था, लेकिन श्रमिकों की घर वापसी इस लॉकडाउन में देखी है, जो शासन प्रशासन के मुंह पर कराराता तमाचा है। लॉकडाउन में मिली त्रासदी से श्रमिकों का सैलाब अगर अपने घरों पर ही बैठ गया, तो भविष्य का विकास पूर्णता थम जाएगा। लेकिन वर्तमान में सरकारों का मुख्य उद्धोष अंत्योदय अब अंत्योत्पीड़न में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां भले ही कोरोना जैसी गंभीर बीमारी महामारी से निर्मित हो हुई हो, लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार तो हमारी सरकार ही है, जो उचित समय पर उचित प्रबंधन नहीं कर सकी। यदि आज भी श्रमिक पैदल चलकर अपने घरों की ओर पहुंच रहा है। चिलचिलाती धूप में अपने आप को झोंक रहा है, तो फिर इस समृद्ध देश का समृद्ध तंत्र थोथा साबित हो रहा है। इस देश की समृद्ध और इतनी लंबी प्रशासनिक संरचना के बावजूद अगर आज बीते 40 दिनों में हम श्रमिकों को उनके मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंचा सके तो किस व्यवस्था में जी रहे हैं हम और अपने भविष्य के लिए क्या उम्मीदें रखें इस व्यवस्था से। मजदूरों की तस्वीरें देश के समृद्ध उद्योग नगरों से निकलकर विभिन्न छोटे-छोटे गांव टोलों से होते हुए अपने नियत ठिकानों की ओर पहुंचने की है। भविष्य के लिए संकेत निश्चित तौर पर श्रम देमन के लिए साबित होंगे और यह भी लिखा जाएगा उस समय में सरकारें इनके लिए उचित प्रबंध करने में सक्षम नहीं थी। श्रमिकों की अंतरात्मा कचोट रही है। कुछ तो अपना सब कुछ छोड़ कर अपने घर की ओर पहुंच रहे हैं, तो कुछ भूखे पेट और सरकार की नाकामी से दबे कंधों से रुदन भरे शब्दों में कह रहे हैं कि अब कभी काम पर नहीं जाएंगे। गांव में जो भी होगा, जैसा भी होगा वहीं पर करेंगे। 1300 किलोमीटर का सफर है तो क्या हुआ साइकिल से 13 दिन 14 दिन या 15 दिन में पहुंच जाएंगे। पैदल चलने वाले कह रहे हैं कि 1 दिन तो पहुंचेंगे ही...।

इन तस्वीरों के लिए शब्द शून्य होते जा रहे हैं। मुझे सरकार लाचार और बेबस दिखाई दे रही है और तंत्र सब कुछ ठीक करने का झूठा आश्वासन देकर सरकारों को केवल ढांझस बंधा रहा है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देश के किसी भी राज्य के पास अपने ऐसे किसी भी नागरिक श्रमिकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते है। देश के श्रम मंत्रालय से गांव के सचिव तक जितने कागजों में मजदूरों के काली स्याही के अंगूठे है, उनसे शायद ही यह चिन्हित किया जा सके की आजादी के सात दशकों में हजारों करोड़ों फूंकने के बाद मजदूरों के पास अपने गांव में कोई काम नहीं है। मजदूरों के पांव के छाले और उनके परिवार की आह के बीच देश के सारे नियम-कायदे और कानून अपनी भूमिका में शून्य दिखाई दे रहे हैं।

कुशलगढ़ के जैन समाज का सतत जारी है सेवाकार्य

जरूरतमंदों और मूक प्राणियों के लिए की भोजन व्यवस्था

माही की गूंज, कुशलगढ़।

कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुके कुशलगढ़ में कई ऐसे परिवार हैं। जिनके खाने पीने तक कि समस्या खड़ी हो गई। वहीं भारी मात्रा में मौजूद पुलिस दल के लिए भी भोजन की व्यवस्था करने करना एक चुनौती था। ऐसे में कुशलगढ़ श्री जैन श्वेतांबर सकल श्री संघ ने इस दिशा में पहल की और न केवल लोगों के लिए बल्कि ड्यूटी पर तैनात जवानों और मूक प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। जैन समाज द्वारा ष्हमारा उद्देश्य भूखों को भोजनष् के तहत 24 मार्च से अब तक 40,000 भोजन पैकेट का वितरण किया है। गुरुदेव की प्रेरणा से अर्पण चोपड़ा,अंशुल गादिया, राजेश सुराना,निखिल चंडालिया, शैलेश लुणावत, अनिल नाहटा, प्रदीप चोरड़िया, सौरभ गादिया, रितेश गादिया, धर्मेंद्र पंचाल, पिंकेश चंडालिया, राज लुणावत आदि युवा इस नेक कार्य में लगे हैं। साथ ही पशुओं के लिए प्रतिदिन 3 से 4 क्विंटल पत्ता गोभी व 10 से 15 किलो आटे की रोटी भी श्री जैन श्वेतांबर सकल श्री संघ द्वारा जन सहयोग से बनवाई जा रही है। नगर सहित पूरे जिले में जैन समाज के इस सेवा कार्य की सराहना की जा रही है।

जिले में सुबह 8 से 2 बजे तक खुला रहा बाजार

दो पहियां वाहनों पर दो सवारी बैठने वालों पर हुई कार्यवाही

माही की गूंज, झाबुआ।

ग्रीन झोन के अंतर्गत आने पर झाबुआ जिले भर में जिला प्रशासन द्वारा आंशिक छूट मिलने पर लोगो में अलग सा उत्साह देखने को मिला। साथ ही इसी बात की खुशी भी रही की पुरा जिला ग्रीन झोन में होने के कारण एक भी कोरोना संक्रमित मरीज पॉजिटिव्ह नही पाया गया है। ऐसे में नगर में भी सभी दूकाने सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुली रही ओर उसके पश्चात् नियम के तहत बंद भी हो गई।

सोमवार को मिली छूट के दौरान नगर मे एक बार फिर से चहल पहल दिखाई दी। वही दूकानदारो ने अपनी दूकानो पर साफसफाई करने के साथ ही थोडा बहुत व्यापार भी किया। जिला प्रशासन से मिली छूट के बाद नगर में व्यापारियो के चहरे थोडे खिले हुये दिखाई दिये। वही नगर मे जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा दूकानो पर सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन भी सख्ती से करवाया गया। वही जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा, पुलिस अधीक्षक विनित जैन, एसडीएम डॉ. अभयसिंह खराडी के साथ ही पुलिस बल द्वारा पुरे शहर में वाहनो से घूम घूम कर निरीक्षण किया। इसी के साथ ही राजवाडा से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दो पहिया वाहनो पर दो सवारी बैठे लोगो को सख्ती से पालन कराने के लिये उन के वाहनो को रोका गया ओर उन के वाहन की चाबी भी निकाल कर खडी करवा दी गई। जिला प्रशासन की सख्ती का विरोध कोई कर नही रहा था लेकिन इनमे से कुछ लोग तो वाकई में परेशान थे ऐसे लोगो को भी नियम के चलते परेशान होना पडा। वही इन लोगो के वाहनो की चाबी भी एसडीएम अभय खराडी के द्वारा निकाल ली गई। उसके बाद जहां गाडी खडी की वहां पर उन्हे यूही छोड दिया गया है। तपती धूम मे लोगो के द्वारा आक्रोश भी जताया गया। जिला प्रशासन की इस कार्यवाही में राजवाडा से लेकर बस स्टेण्ड छतरी चौक तक पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। वही मौके पर इस कार्यवाही में जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा एव पुलिस अधीक्षक विनित जैन के द्वारा धरपकड की कार्यवाही चरम पर थी वही दूसरी ओर अन्य सामान्य लोग भी परेशान होते नजर आये जिसमें कई लोग तो सही मायने मे अपने कामो से जाने वाले लोग भी परेशान हुये। वही लोगो के द्वारा आक्रोश भी व्यक्त किया गया। जिस में कई लोगो ने यह तक कहा कि जो लोग जानबूझ कर नियमो को तोड रहे है उन्हे पकडना सही है लेकिन यदि कोई शासकीय कर्मचारी एवं जरूरतमंद यदि अपने ईलाज के यदि जाना है तो उसे कम से कम उन्हे किसी ना किसी के साथ आने पडता है जिसे दो पहिया वाहन चलाना आता है। ऐसे लोगो को भी जिला प्रशासन की सख्ती का सामना करना पडा। वही कई लोगो मे नाराजगी भी जताई कि जिला प्रशासन द्वारा दी गई छूट में यदि किसी को दो पहिया वाहन चलाते या फिर यदि किसी को कोई बैंक या फिर अस्पताल ईलाज के लिये जाना पडे तो वो क्या करेगा क्या वह पैदल जायेगा। इस कार्यवाही मे कुछ ऐसे लोगो को इस कार्यवाही का शिकार होना पडा जो बैंक जा रहा था, कोई जिला अस्पताल ईलाज के लिये जा रहा था ऐसे लोगो को भी परेशान होना पडा। इसके लिये जिला प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिये।

जिला प्रशासन द्वारा की गई सख्ती से कार्यवाही ।

बैंको के बाहर खडे ग्रामीणों की लगी भीड।

सोश्यल डिस्टेंसिंग का नही हुआ पालन

लॉक डाउन के चलते छूट देने के बाद नगर मे बैंको के बाहर कुछ इस तरह का नजारा दिखाई दिया जिसमें ग्रामीण लोगो के द्वारा सोश्यल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उडाई गयी। वही बैंको के बाहर एक लंबी कतार सी लग गई। जिसमें ग्रामीणो के द्वारा पास पास खडे हुये दिखाई दिये। इस ओर ना ही बैंक के कर्मचारियो के द्वारा ध्यान दिया ओर ना ही बैंक में खडे जनता द्वारा इन ग्रामीणो को सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। जहां एक ओर अपना झाबुआ जिला ग्रीन झोन में सुरक्षित है वही डर लगने लगा है कि कही ऐसे कारनामो के कारण कही जिला ग्रीन झोन से बाहर ना आ जाये।

सख्ती से पालन कर दो पहिया वाहनो पर बैठी दो सवारी वाले वाहनो के चालानी कार्यवाही के निर्देश भी दिये। लगभग 100 से अधीक लोगो की दो पहिया वाहनो को पकडकर चालानी कार्यवाही भी की गई।

नियमो का सख्ती से हुआ पालन कई अन्य लोग हुये परेशान

जहां एक ओर नगर में इस तरह की

मनरेगा, मजदूर और जिला: कब और कहां तक?

माही की गूंज, झाबुआ।

मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। अंचल के लाखों की संख्या में मजदूर समीपस्थ प्रांत गुजरात के महानगरों में मजदूरी हेतु जाते रहे है। कई तो लॉकडाउन से पूर्व तक वहीं के रहवासी कथित रूप से बन चुके है। कई मजदूर ऐसे भी थे जो वर्षभर में एकाध बार कुछेक दिनों के लिए ही अंचल में आते थे। जबकि इन मजदूरों के नाती-रिश्तेदार और जमीन-जायदाद भी अंचल में ही है। मूल रूप से जिले के रहने वाले मजदूर गुजरात जाकर आधुनिकता से भी जुड़े थे और सम्पन्नता की ओर भी अग्रसर थे। लॉकडाउन लगने भर से मजदूरों का जो लौटने का क्रम जारी है। यह सरकार द्वारा गरीबों के नाम चलाई जा रही योजनाओं की पोल खोलने का यक्ष प्रमाण है। स्पष्ट है सरकारों द्वारा इनके हितों में किए गए कार्य नाकाफी साबित हुए है। जिले के लाखों मजदूर अब तक लौट चुके हैं, तो कुछ के लौटने का सिलसिला जारी है। संभावना है आने वाले दिनों में ओर भी लोग आए।

जिला प्रशासन के फरमान अनुसार लौटने वाले मजदूर जो शत-प्रतिशत ग्रामीण अंचल के है, उनके लिए मनरेगा के कार्य प्रारंभ किए जाएं। भ्रष्टाचार का दल-दल बन चुकी, मनरेगा में ईमानदारी से कार्य होता तो यह मजदूर जिले से जाते ही नहीं, किंतु यह इनकी खराब किस्मत का ही परिणाम है कि मनरेगा व अन्य योजनाएं जो इनके हित के लिए बनाई गई थी, में भ्रष्टाचार रूपी दीमक लग गई और समय के साथ इन योजनाओं को खोखला करती ही चली जा रही है। प्रदेश में ही पिछले डेढ़ वर्षों में दूसरी बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है, परंतु सरकारों ने इनकी हितार्थ ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे कि अंचल के लोग यहीं रूककर ईमानदारी से रोजगार प्राप्त कर सके। कांग्रेस की बनी सरकार के समय तो अंचल को तोहफे में जिला स्तरीय ऐसा अधिकारी मिला, जिस पर आरोप है कि वह सीधे पंचायत में पहुंचकर रिकॉर्ड ही जप्त कर लेता और फिर भांजगढ़ी के माध्यम से पंचायत स्तरीय जिम्मेदार इसके चंगुल से छूट पाते। बताते तो यह भी है कि दलालों से घिरा यह अधिकारी शौचालय तक में मलाई ढूंढता फिरता है। बिना लिए-दिए पंचायत स्तर के कोई कार्य नहीं होते और इसी से आक्रोशित होकर कांग्रेस सरकार में कांग्रेस समर्थित सरपंच आदि भी कांग्रेस के ही बड़े नेताओं के सामने नाराजगी व्यक्त कर चुके है। आरोप के संबंध में बताते है जिला स्तरीय इस अधिकारी के संबंध कांग्रेस सरकार के किसी मंत्री से थे। उन्हीं की कृपा थी कि मीडिया द्वारा उजागर करने तथा सरपंचों द्वारा आक्रोश व्यक्त करने के बावजूद जिलाधिकारी अपने पद पर न सिर्फ बना हुआ था अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले निर्माण कार्यों में जमकर कमीशन रूपी मलाई मार रहा है। कांग्रेस सरकार के पूर्व 15 वर्ष तक भाजपा सरकार ने भी प्रदेश में कब्जा जमाया हुआ था, किंतु पलायन की स्थिति कभी सुधरी नहीं और न ही अपनी सरकारों ने कभी मजदूरों, गरीब ग्रामीणों को उद्योगों की अपेक्षा आर्थिक उन्नति की ओर धकेला।

पलायन जो मजदूरों की आवश्यकता और मजबूरी बना हुआ था, कोरोना ने इस पर जमकर प्रहार किया। जिले में लौटने वाले मजदूरों को लिए प्रशासनिक फरमान मनरेगा को लेकर जारी हो चुका है, किंतु तंत्र में बैठे भ्रष्टों पर कब, कौन, कैसे अंकुश लगाएगा जिससे कि इन मजदूरों को जिले में इनके हक की मजदूरी व रोजगार ईमानदारी से प्राप्त हो सके।

सम्मान को बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी

माही की गूंज, खवासा। दिबीत भटेवरा

देश में डॉक्टरों का सम्मान प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर भगवान श्रीराम स्वयं ने वैद्यराज को मरीजों के लिए भगवान का अवतार बतलाया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के बाद देश में सफाइकर्मियों के प्रति भी देशवासियों में सम्मान की भावना जागृत हुई है, लेकिन वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बाद के लॉकडाउन के दौरान देशवासियों के मन में पुलिस के प्रति आम धारणाओं में भी बदलाव हुआ है। पुलिस की इस संकट के समय देश के प्रति सेवाओं को देशवासियों ने नमन किया है, उनके प्रति सम्मान दर्शाया है और डॉक्टर, सफाईकर्मी और पुलिसकर्मी को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दी गई है। देश के कई हिस्सों में पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी के दौरान जिस मानवता का परिचय दिया, वह काबिल-ए-तारीफहै। कई जगहों पर भूखे को खाना खिलाया, बेसहारा का सहारा बने तथा कई मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की। इस प्रकार देखा जाए तो पूरे देश में पुलिस की छवि में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ। उनकी छवि में निखार आया, लेकिन यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि, अब वह अपनी इस छवि को बनाए रखें। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी कहा था कि, अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो, लेकिन आम जनता के मन में पुलिस के प्रति कोई भय ना हो।

खवासा में लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। लॉकडाउन के दौरान जहां पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई और कई बार प्रतिष्ठित व सम्मानीय व्यक्तियों को भी फटकार लगाने से

नहीं चूके। वहीं फटकार खाने के बावजूद प्रतिष्ठित व सम्मानीय व्यक्तियों ने पुलिस के इस कदम की तारीफकी की।

लॉकडाउन के तीसरे चरण में जब आम जनता के लिए दोपहर 2 बजे से सुबह 8 बजे तक बिना वजह घूमना वर्जित है, लेकिन 5 मई की रात्रि लगभग साढे 10 बजे बाजना रोड पर दो अवैध शराब विक्रेताओं के मध्य जमकर गाली-गलौज व अपशब्दों की बौछार हुई। जिसे देखकर पूरे मोहल्लेवासी घरों के बाहर आ गए और मामला लठबाजी तक आ पहुंचा था। जिसके बाद पुलिस आई, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर जनता को निराशा हासिल हुई, जो पुलिस लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में आम जनता के साथ भी इतनी सख्ती से पेश आ रही थी कि, लोग घरों के बाहर ओटले पर बैठने में भी डरने लगे थे। वहीं पुलिस अवैध शराब विक्रेताओं के सामने समझाइश देने की मुद्रा में आ गई थी और अवैध शराब विक्रेता पुलिस के सामने ही एक-दूसरे को गालियां दिए जा रहे थे। पुलिस के सामने भी शराब के नशे में अपनी मर्दांगी दिखा रहे थे। यह सब देखने के बाद आम लोगों में एक बार फिर पुलिस के प्रति निराशा देखी गई और आम जनता के बीच यही प्रतिक्रिया रही कि, पुलिस शराब दुकान खोलने के पूर्व ही अवैध शराब विक्रेताओं के आगे नतमस्तक हो गई और मुख्यमंत्री के कथन के विपरीत व्यवहार करने लग गई। जहां अपराधी पुलिस से बेखौफहै तथा आम जनता पुलिस से भयभीत भी है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जो छवि देखी गई उसे बनाए रखना पुलिस की ही जिम्मेदारी है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं पुलिस की साख पर आघात पहुंचाती है और कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस स्वयं जिम्मेदार है।

फोटो क्र. 554 केप्शन- कोरोना में पुलिस की मानवीयता को हर किसी ने सराहा अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि, वे अपना सम्मान बनाए रखे ।

लॉकडाउन में पूर्णतः प्रतिबंधित गुटखा, पाउच की जमकर हो रही कालाबाजारी

माही की गूंज, खवासा।

प्रशासनिक नुमाइन्दें कार्रवाई के बजाय बहती गंगा में धो रहे हाथ

रोग प्रतिरोधक क्षमता गुटखा, पाउच, तंबाकू व शराब का सेवन करने से कम होती है एवं गुटखा, पाउच व तंबाकू खाकर थूकने से गंदगी भी फैलती है। कोरोना वायरस के चलते सरकारों ने भले ही ठोस कदम उठाकर इसे लॉकडाउन के साथ ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार को भी टैक्स के रूप में करोड़ों का नुकसान हुआ। तो वहीं सरकार के प्रतिबंध के बाद शराब, तंबाकू व गुटखा, पाउच बेचने वाले माफिया ऐसे सक्रिय हो गए कि, उन्होंने अभी तक के इतिहास में इतनी महंगी यह प्रतिबंधित सामग्री बेचकर इतना मुनाफा नहीं कमाया जो इस लॉकडाउन के दौरान। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी उसी की नाक के नीचे धड़ल्ले से यह कारोबार चलता रहा और अब भी यह कारोबार चल रहा है। वैसे तो बड़ी कशमकश के साथ बुधवार को प्रदेश में रेड झोन व कंटेनमेंट एरिया को छोडकर शराब की सभी दुकानें खोल दी गई। तंबाकू गुटखा, पाउच के बड़े स्टॉकिस्टों ने करोड़ों के न्यारे-न्यारे गुटखा पाउच व तंबाकू में कर लिए। तो वहीं जिनके जिम्मे इस कारोबार को रोकने का कार्य था, उन्होंने भी कार्यवाही करने की बजाय इसके कारोबारकर्ताओं को संरक्षण देकर पकड़ कर कार्रवाई करने के अपने न्यारे-न्यारे भी कर लिए।

कुछ ऐसा ही मामला माही की गूंज के विशेष सूत्रों के माध्यम से सामने आया। तो गूंज प्रतिनिधि ने इसकी पूरी पड़ताल की और वीडियो भी प्राप्त किया। शनिवार को बाजना (रतलाम) निवासी रौनक पिता रमेश जैन, बड़ीसरवा (राज.) निवासी विजय टेलर के साथ पेटलावद निजी कार से गए थे। पेटलावद पेट्रोल पंप पर कार खड़ी कर पेटलावद के किसी बड़े व्यापारी से रौनक की मोबाइल पर बात हुई और स्कूटी से नेचरल गोल्ड के नाम से छपे सफेद 5 बोरे में विमल ब्रांड का गुटका, पाउच जिसमें 250 पैकेट व अन्य दो बोरों में विमल गुटका में शामिल कर खाने वाला तंबाकू का पाउच लेकर आए। उक्त पाउच के पैकेट का सामान्यतः 120-125 रुपए तक पैकेट बाजार में मिलता था। प्रतिबंध के बाद यह 4-5 गुना भाव तक बिक रहा है। रौनक, विजय टेलर के साथ उक्त प्रतिबंधित गुटखा, पाउच पेटलावद से बामनिया होते हुए खवासा बायपास से बाजना जा रहा था कि, मुखबिर के माध्यम से बाजना क्षेत्र का रहवासी जिसकी रिश्तेदारी व पहचान बाजना से लेकर बामनिया व पेटलावद तक है, पुलिस आरक्षक राकेश खवासा चौकी पर पदस्थ है, को मुखबिर के माध्यम से पता चला कि, रौनक की कार में गुटखा, पाउच जा रहा है। अगर कार को पकड़ ली गई तो बड़ा पैसा रौनक से मिल सकता है। जिसके बाद राकेश खवासा चौकी पर पदस्थ अन्य एक पुलिस जवान पवन को साथ ले गया और खवासा के बामनिया बायपास पर स्टेडियम के समीप दोनों पुलिस जवान ने कार को रोका और कार में से सफेद बोरों में भरे

मुट्ठे पाउच से भरे बोरे के साथ रौनक जैन का बनाया पुलिस आरक्षक ने वीडियो।

माही की गूंज EXCLUSIVE

विमल पाउच के पांचों कट्टों को बाहर निकाल कर आरोपी रौनक का बोरों के साथ पुलिस जवान राकेश ने 39 सेकंड का वीडियो बनाया। जिसमें आरोपी का नाम, बोरों में क्या है, कहां से लाया? पूछा जिसके बाद काफी समय तक लेन-देन की बात चलती रही। 20-25 हजार रुपए देने की बात रौनक ने मामले को रफा-दफा करने हेतु कहीं पर बामनिया व्यापारी उर्फमुखबीर यह जानता था कि, यह माल एक लाख रूपए से अधिक का है। माल को बचाने एवं एफआईआर से बचने के लिए कम से कम एक लाख रुपए तक दे सकता है, यह बात पुलिस जवान को बताई। वही रौनक की जेब में 20-25 हजार रूपए ही थे, तो मामला मुखबिर के माध्यम से पुलिस ने रौनक की जेब में जो पैसे थे वो और उन पैसों के साथ विमल, गुटखा, पाउच से भरे दो बोरे जिसमें सौ पैकेट गुटखा, पाउच जिसकी खेरची मूल्य वर्तमान के मान से 50-60 हजार रुपए है, पुलिस जवान ने विमल पाउच से भरे दो बोरे ले लिए व 3 बोरे विमल गुटखा पाउच को छोड़कर रौनक एवं विजय को रवाना कर दिया। उक्त मामला सिर्फपुलिस, मुखबिर व रौनक के बीच का होता तो शायद यह माही की गूंज तक भी उजागर नहीं होता। उक्त पूरे मामले में विजय टेलर ने विभीषण की भूमिका निभाने का सामने आया। विजय टेलर ने ही रौनक के साथ रहकर उसे भी यह पता नहीं चलने दिया कि, वह उसकी ही कब्र खोदने जा रहा है। मौका मिलते ही पेटलावद के किसी व्यापारी को सूचना देकर पुलिस जवान राकेश को मुखबिरी करने की बात कही।

विमल गुटखा पाउच के बोरे से भरी कार को पकड़ने के बाद कुछ नगदी तथा सौ पैकेट विमल के लेकर लेन-देन का मामला निपटा। कार जाने के बाद बामनिया का मुखबिर व्यापारी खवासा आया और राकेश ने वह सौ पैकेट उसे दे दिए और उसके बदले उसे पैसा देने की बात हुई। बामनिया जाने के बाद बोरो को खोला तो उसमें सिर्फविमल गुटखा पाउच ही निकला पर उसके साथ मिलाने वाला तंबाकू पाउच नहीं निकला जो 2 बोरों में कार के अंदर ही पड़ा था, बिना तंबाकू पाउच के उक्त विमल का कोई औचित्य नहीं था, तो विभीषण विजय ने दांव खेल तीसरे के माध्यम से वह विमल पाउच बड़ीसरवा मंगवा लिए और विजय सभी को रौनक व पुलिस की सांठगांठ होने की बात कहता रहा। जिससे यह बात उजागर होकर मुखबिर के माध्यम से माही की गूंज तक पहुंची। बिना तंबाकू पाउच के, विमल गुटके के सौ पैकेट के पुलिस को कितने पैसे लिए-दिए यह तो विजय टेलर, बामनिया का व्यापारी व दो पुलिस जवान ही बता सकते है। पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली उजागर होकर विजय टेलर के कारनामे भी सामने आए हैं।

इस संबंध में पुलिस चौकी प्रभारी से चर्चा हुई तो वह अपने जवान को बचाने की ही मुद्रा में दिखाई दिए। पर गूंज की सूचना के बाद फिलहाल राकेश आरक्षक को थांदला थाने पर रवानगी दे दी है। अब देखना है कि पूरा मामला सामने आने पर पुलिस कप्तान दोनों आरक्षकों के साथ आरोपी रौनक जैन, विजय टेलर, बामनिया का मुखबिर व्यापारी व पेटलावद में अब तक भी इतने बड़े पैमाने पर गुटका पाउच का स्टॉक कर बेचने वालों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करते हैं?

साहित्यकार डॉ चंचल की ताजा कृतियां धरोहर का हुआ विमोचन

माही की गूंज, झाबुआ। साहित्यकार डॉ रामशंकर चंचल के ताजा कृतियां धरोहर 1,2,3 का विमोचन एसबीआई मुख्य प्रबंधक हेमेंद्र कुमार दधीच के कर कमलों से संपन्न हुआ। विमोचन करते हुए दधीच ने कहा यह सुखद अवसर है कि मैं डॉ चंचल की ताजा कृतियां धरोहर 1,2,3 का विमोचन कर रहा हूं। यह उनके

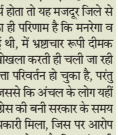

साहित्यिक साधना और उपलब्धियों का जीवित प्रमाण है अभी तक 30 -35 वर्षों में उनकी साहित्यिक साधना की अखबारी कतरनों का अद्भुत समावेश है। जो यह बताता है कि डॉक्टर चंचल आज से 25 वर्ष पूर्व भी इसी तरह से सतत साहित्य साधना में लगे थे जैसे आज हैं ऊंचाइयों पर मुकाम पाना तो सहज होता है किंतु उसे बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम है ।और यह मुश्किल काम डॉक्टर चंचल ने किया है ।डॉक्टर चंचल आज झाबुआ ही नहीं बल्कि प्रदेश व देश के लिए गौरवशाली है ।मुझे प्रसन्नता है कि इस विमोचन का शुभ अवसर मुझे मिला ।इसी अवसर पर डॉक्टर चंचल ने मुख्य प्रबंधक हेमेंद्र कुमार दधिच का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह एक सुखद अवसर था कि मैंने मुख्य प्रबंधक हेमंत कुमार दधीचि के हाथों मेरी कृतियों का विमोचन कराया।

मारूति नगर के एक मकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान

माही की गूंज, झाबुआ।

शहर के हुड्डा क्षेत्र मारूति नगर कॉलोनी में नगरपालिका कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी भावसिंह जमरा के भाई माधुसिंह जमरा के मकान में, जो सूना पड़ा था। अचानक शार्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से मकान में रखा अनाज, पलंग, अन्य घरेलू सामग्री और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर पूरी तरह से खराब हो गए। मकान मालिक को करीब 1 लाख रू. का नुकसान हुआ।

पूरा मामला इस प्रकार है कि 4 मई, सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे माधुसिंह जमरा, जो फिलहाल उनकी पत्नि एवं परिवार के साथ आलीराजपुर जिले के नानपुर के माछलिया गांव में रह रहे है। अचानक मकान में लगे बिजली के फ्यूज में शार्ट-सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने का पता काफी देर तक मकान सूना होने से आसपास के रहवासियों सहित पास ही रहने वाले उनके भाई भावसिंह जमरा को नहीं लग सका। जब मकान के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा और आग की लपटे तेज होने लगी, तो आसपास के रहवासियों को पता चलने पर उन्होंनें प्राथमिकता में पानी की मोटर लगाकर पाईप से आग को बुझाने का प्रयास किया।

समीप रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मंजु वर्मा ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी। पुलिस कंट्रोल रूम से फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर नगरपालिका की एक फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर संपूर्ण आग पर काबू पाया, लेकिन इससे पूर्व ही मकान के डमों (कोठियां) में रखा अनाज (गेहूं), पलंग, बिस्तर, अन्य घरेलु सामग्रीयों के साथ विषेष रूप से मकान के पड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जल गए। दीवार, छत और पंखे भी काले पड़े गए। माधुसिंह के भाई भावसिंह के अनुसार करीब एक लाख रू. का नुकसान हुआ। जिसकी रिपोर्ट (सूचना) उनके द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई है।

मजदूरों के अच्छे 'कैसे' दिन आ गए

माही की गूंज, झाबुआ।

यह फोटो मजदूरों के अच्छे दिन आने का है का दिवा स्वप्न है। वर्ष 2013 भाजपा ने अपने चुनावी कैपेन में अच्छे दिन आने वाले है का नारा दिया था। उस नारे के 7 वर्ष के बाद कोरोना महामारी के चलते मजदूरों के अच्छे तो नहीं परंतु कैसे दिन जरूर आ गए है। पिटोल बार्डर पर खड़ी यह बस जिस पर अच्छे दिन आ गए है लिखा हुआ है। इसके ठीक सामने अपनी उजड़ी गृहस्थी को समेटे हुए रोड़ पर बैठे मजदूरों की व्यथा दिखाई दे रही हैं। जो अच्छे दिन लिखी बस की तरफदेखना तक नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके कैसे दिन आ गए, इसकी आहट को कोई सरकार, नेता और चुनावी कैंपेन के नारे दूर नहीं कर सकते हैं।

आखिर वही हुआ जिसका डर था

प्रशासनिक सजगता से टल सकता था मामला

माही की गूंज, झाबुआ।

अब तक ग्रीन जोन रहे झाबुआ जिले के लिए निश्चित ही यह खबर चिंताजनक है कि, नयागांव (नीमच) से 29 अप्रैल को आई दाजी बस में सवार महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस मामले में कंडक्टर की रिश्तेदारी के साथ नीमच जिला प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिसमें उन्होंने बगैर जांच के ही

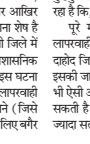

मजदूरों के साथ दाहोद निवासी दो भाई के परिवार को बस में झाबुआ भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। माही की गूंज न्यूज पोर्टल ने पूर्व में ही लिख दिया था कि, 'लापरवाही का परिणाम बुरा हो सकता है' और आखिर वही हुआ जिसका डर था। अभी एक रिपोर्ट आना शेष है और अगर वहं रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो भी जिले में तो कोरोना का खाता खुल ही चुका है। थोड़ी सी प्रशासनिक चूक ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया है। इस घटना में एक और जिला नीमच जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जिसने केवल अपना पीछा छुड़ाने (जिसे स्थानीय भाषा में माथा उतारनी कहा जाता है) के लिए बगैर जांच किए मजदूरों के साथ दाहोद के कोरोना संक्रमित परिवार को भेज दिया। वहीं जिला प्रशासन की लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता है जो अब तक प्रेस में गोलमोल जानकारी ही देता आया है। प्रशासन ने पूर्व में जो जानकारी 45 सदस्यों की दी थी, जिसमें बताया गया था थांदला क्षेत्र के 10 मजदूर जिसमें 5 खवासा क्षेत्र के पाटडी ग्राम के हैं और मजदूरों के सरनेम भी नहीं दिए गए थे, तो वही खवासा क्षेत्र के खेरियापाडा के मजदूर जो इसी बस में आए थे, के नाम भी नहीं थे। तो वहीं जिस बंशी परिवार को पाटडी का बताया जा रहा था, वे डॉक्टर की पुष्टिगुसर जानकारी सामने आ रही है। उसमें यह बताया जा रहा है कि, बंशी परिवार अलीराजपुर जिले का है।

पूरे मामले में निश्चित रूप से बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। जिसके लिए नीमच,झाबुआ व दाहोद जिला प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है और इसकी जांच की जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में भी ऐसी और असावधानियां होगी और वह घातक सिद्ध हो सकती है। खतरा अभी टला नहीं है बल्कि अब तो और ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है।

रोजगार के लिए पलायन: पहले चुनावी मुद्दा, अब कोरोना का

माही की गूंज। संजय भटेवरा

झाबुआ जिला एक बड़ा श्रम निर्यातक जिला माना जाता है। यहां से बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में देश के विभिन्न राज्यों में दूर-दूर तक जाते हैं और वहां मजदूरी करके बारिश में अपने घरों की ओर लौटते हैं। आजाद हिंदुस्तान के लगभग हर लोकसभा, विधानसभा और स्थाई निकायों के चुनाव में यह चुनावी मुद्दा रहा है और हर विजयी उम्मीदवार ने स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा आम जनता से किया। लेकिन इसे जिले की बदनसीबी ही कही जाएगी कि आजादी के सात दशक बाद भी जिले के श्रमिकों का पलायन न केवल जारी है बल्कि प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है।

यह स्थिति तब भी जारी है। जब सरकार, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी (मनरेगा) जैसी योजना की सफलता का जोर-शोर से दावा करती रही है। इस पलायन के कारण जिले की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और शायद यही कारण है कि, जिले में शाला त्यागी बच्चों का एक बडा आंकड़ा भी मौजूद है।

वर्तमान में जारी वैश्विक महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। लॉकडाउन को लगभग डेढ़ माह बीत जाने के बावजूद मजदूरों को घर पहुंचाना, प्रदेश की सरकार के लिए एक बडा सिरदर्द बना हुआ है। लॉकडाउन के पहले चरण में तो जैसे-जैसे करके इन लोगों ने यह समय निकाल लिया, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में इनके हौंसलों ने दम तोड़ दिया। सरकार के तमाम दावों-प्रतिदावों के बीच वर्तमान में यह स्थिति है कि, हजारों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में आज भी फंसे हुए हैं। जहां उन्हें रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई लोग तो भूखे और प्यासे 1 हजार से 15 सौ किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने घरों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि ये मजदूर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके भी मदद की अपील कर रहे हैं। वहीं कुछ थांदला-खवासा क्षेत्र के मजदूरों ने माही की गूंज कार्यालय में भी फोन करके मदद की अपील की है। लॉकडाउन का डेढ़ माह से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद अभी भी जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में पलायन पर गए मजदूरों की वास्तविक संख्या का कोई अता-पता नहीं है, जबकि शासन स्तर पर लॉकडाउन लगते ही सभी पंचायतों से यह आंकड़ा एकत्र कर लिया जाता तो, इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यही नहीं जो मजदूर जहां है, वहीं पर सरकार भी मदद पहुंचा सकती थी, लेकिन किसी भी पंचायत स्तर पर यह कार्य नहीं किया गया। यही नहीं सरकार अगर चाहे तो पंचायत स्तर पर ही मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले श्रमिकों का पंजीयन अनिवार्य कर दे। जिससे प्रत्येक पंचायत से कितने मजदूर कहां और कितने दिनों के लिए जाते हैं, इसकी जानकारी रहे। तो आपातकालीन स्थिति में आसानी से यह पता चल सकता है कि, किस गांव के कितने मजदूर, किस राज्य में है। ऐसी स्थिति में न केवल तत्कालीन सहायता पहुंचाई जा सकती है वरन् संकट की स्थिति में मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी भी की जा सकती है। वही कोरोना संक्रमण की चौन को तोड़ने के लिए पुख्ता जानकारी होने पर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी आधार बनाकर संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सकती है।

उम्मीद है कोरोना महामारी से सबक लेते हुए भविष्य में अगर इस प्रकार की सावधानियां प्रशासन अपनाएं तो निश्चित ही आपातकालीन स्थिति में मददगार साबित हो सकती हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422